12/03/2018/1400/MS/AG/1

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 2.00 बजे अपराह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

12/03/2018/1400/MS/AG/2

प्रश्न संख्याः42

अध्यक्षः श्री अरुण कुमार (अनुपस्थित)।

12/03/2018/1400/MS/AG/3

प्रश्न संख्याः 43

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके मुताबिक इस सिविल हॉस्पिटल को बनाने की लागत लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये है और अभी तक लगभग डेढ़ करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि यह 50 बिस्तरों वाला सिविल हॉस्पिटल बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में है और यह बहुत बड़े एरिया को कैटर करता है इसलिए क्या आप इसके लिए फण्ड्ज अति शीघ्र उपलब्ध करवाएंगे? बजट में वैसे आपने कुछ प्रावधान किया भी है लेकिन उतने पैसे से काम बनने वाला नहीं है। क्या जरूरत पड़ने पर आप इसके लिए बजट का प्रावधान करते रहेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यहां पर जानना चाहा है कि किहार में जो सिविल हॉस्पिटल निर्माणाधीन है जिस पर लगभग 5 करोड़ 45 लाख 75 हजार रुपया खर्च होने वाला है और लगभग 1 करोड़ 48 लाख 2 हजार रुपये इसके निर्माण के लिए जमा हुए हैं तथा लगभग 3 करोड़ 79 लाख 73 हजार रुपये अभी इस पर खर्च होने हैं। माननीय सदस्या ने चाहा है कि इस अस्पताल के निर्माण की गति तेज होनी चाहिए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। इस बार के वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित बजट में प्रावधान भी किया गया है और उसमें लगभग 50 लाख रुपया रखा गया है। अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे-जैसे इसका काम और आगे बढ़ेगा तो धन की उपलब्धता पर धन की व्यवस्था की जाती रहेगी।

12/03/2018/1400/MS/AG/4

प्रश्न संख्याः 44

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके "सी" भाग से मैं शुरू करूंगा। All the mining leases granted in and around Chakki Khad have been properly flagged. अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कल शाम 5.00 बजे मैं वहां से चला हूं and there is not one mining lease which has been flagged और कुछ एक-दो फ्लैग जो लगे हुए हैं वे सरकारी भूमि पर लगे हुए हैं। अगर आप मौके पर जाकर देखेंगे, if you see the circumstances where these leases are, इनमें इतनी अवैध माइनिंग हो चुकी है और इतने बड़े-बड़े टिब्बर बन चुके कि आप वहां फ्लैग लगा ही नहीं सकते हैं। दूसरा, आपका जवाब आया that there are about 40 stone crushers installed in Chakki Khad falling in Nurpur and Indora Sub Division, out of which 22 have been closed and 18 are running legally. अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया है कि इतने क्रशर बन्द हो गए हैं और इतने चल रहे हैं तो पिछले तीन साल पहले भी ये क्रशर बन्द हुए थे। मैं तीन साल की हिस्ट्री की बात बाद में करूंगा। फिर जब अखबार में खबर लगी तो उस समय के वहां के एस0डी0एम0 साहब की स्टेटमैंट लगी कि ये सारे क्रशर्ज अवैध हैं and they have got no relevant documents with them. इसलिए हमने इनका बिजली का कनैक्शन काट दिया है and directions have been issued to the Police Department to lift the generators from the sites.

12.03.2018/1405/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 44ः----जारी--------

और एक महीने के बाद वही सारे क्रशर चल पड़ते हैं। उनको फिर यह परमिशन कहां से आई? अब इनमें क्या है, जो आप बता रहें हैं कि लिगली 18 यूनिट चल रहे हैं। मैं उदाहरण

देता हूं कि जैसे कि शिवा स्टोन क्रशर है, उसका नाम अब न्यू शिवा कर दिया। एक छोटे भाई के नाम तो दूसरी लीज़ बड़े भाई के नाम कर दी । इस प्रकार के मैं आपके पास 10 केस ला सकता हूं। कान यहां से नहीं पकड़ा तो वहां से पकड़ लिया and they have obtained fresh permissions from the department but खिलाड़ी वही है लेकिन परमिशन नई आ गई ह। और इसमें modus operandi कितना है आप सोच भी नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि ये बताएं कि ऐसे कितने क्रशर हैं जिनके दो-दो यूनिट्स हैं और ऐसे कितने क्रशर हैं जिनकी एक यूनिट की परमिशन है लेकिन वहां पर बैल्टें 6-6 लगी हुई हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि यूनिट एक है लेकिन 6 चल रहे हैं। ऐसे कितने यूनिट वहां पर हैं जो ये काम कर रहे हैं?

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता बताई है उसके ऊपर पहले दिन से ही सरकार ने आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक कमिटमैंट के साथ कि इलीगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश में बन्द होनी चाहिए उसके कुछ उदाहरण आपके सामने भी है, लेकिन जो आदरणीय राकेश पठानिया जी ने बोला है, मुझे लगता है कि जैसे ये प्रॉपरली फ्लैग लगाने की बात कह रहे हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं कि वहां पर फ्लैंग लगे तो लगे कहां? आपकी बात बिल्कुल ठीक हो सकती है। मैं विभाग को इस बात का निर्देश दूंगा कि यह जो फ्लैग का विषय आपने उठाया है, फ्लैग जो आपके लगे हैं, ये फ्लैग इस तरीके से लगें कि बड़ी दूर से हमें पता लगे कि यह कौन सी जगह है। आपने चिन्ता जाहिर की है कि आज एक भाई इस काम को रहा है और जब वह डिफाल्टर हो जाता है तो वह दूसरे भाई के नाम उसको करता है। यह बिल्कुल सही बात है।

12.03.2018/1405/जेके/एजी2

तो बड़ी जल्दी हम यह काम करने वाले हैं कि किसी के भी ब्लड रिलेशन में कोई भी डिफाल्टर होगा तो उस ब्लड रिलेशन में उस परिवार के किसी भी व्यक्ति को यह काम नहीं करने देंगे। इसको हम बदलेंगे। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। हमने यहां से कोई भी बैकडोर एन्ट्री नहीं रखी है। हमारे पास इस प्रकार के काम करने वाला आ नहीं सकता है। इसलिए जो आपकी चिन्ता है वही मेरी चिन्ता है। इसी के साथ एक बात और मैं आपको

कहना चाहूंगा कि यह जो आपने, मैंने तो कोशिश की है सारी चीज़े पढ़कर बताने की लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। जहां-जहां आपको कमियां लगती हैं, उन सारी चीजों को देखेंगे और ठीक करेंगे। एक आपने पूछा कि क्रशर की कितने की परमिशन है और कितने चल रहे हैं? जितनी हमने परमिशन दी हुई है उतने ही क्रशर चल रहे हैं। फिर भी आपके ध्यान में, जैसे कि अभी आपने बोला कि एक बैल्ट की जगह छः बैल्ट है। अगर ऐसे विषय है तो कृपया आप बताएं तो उनके ऊपर मैं पूरा ध्यान दूंगा।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से बड़ा स्पैसिफिक सा प्रश्न पूछा है और इन्होंने मुझे ज़वाब भी बढ़िया दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप तो सरकार में नये हैं परन्तु किस बदमाशी से यह माफिया यहां पर काम कर रहा है। पिछली सरकार ने क्या किया कि जिनके पास लीज़ नहीं थी उन्होंने फिशिंग वालों से फिशिंग पौंड्ज़ की परमिशन ले ली। मेरे पास पूरी सूची है। जो फिंशिग पौंड्ज़ की वहां पर परमिशन दी गई। यह पिछली सरकार के दौरान हुआ। मैं जानना चाहूंगा कि इनमें से जो फिशिंग पौंड्ज़ वाले क्रशर हैं, ये भी आज के दिन काम कर रहे हैं। मैंने फिशिरीज डिपार्टमैंट से आर.टी.ए. मांगी कि कितनी मछली पैदा हुई और कितनी फिशिंग पौंड्ज की परमिशन दी गई ? उनका ज़वाब आया शून्य। एक किलो तक मछली पैदा नहीं हुई। ये जो बड़े मगरमच्छ यहां पर फिंशिग पौंड्ज की वजह से काम कर रहे हैं, क्या इनकी सूची आपके पास है?

12.03.2018/1405/जेके/एजी/3

क्या आप इसकी सूची हमें उपलब्ध करवाएंगे? और ये जो क्रशर्ज जो आपने बताया कि लिगली चल रहे हैं मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इनके ऊपर जुर्माना लगा हुआ है और इनके ऊपर कितना जुर्माना है? इनको जुर्माना हाई कोर्ट में भी है, मैटर सब-ज्युडिस भी है। मैं, मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या आप अवेयर हैं कि आज से 12 साल पहले चक्की खड्ड के ऊपर हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया एक साथ अधिक सप्लिमेंटरी मत पूछें। माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दें।

उद्योग मंत्रीः माननीय सदस्य, आप प्यार से पूछें क्या बात है?आप हमारे मित्र हैं और दूसरे हमारे दल के हैं। धीरे बोलेंगे तो लोग समझेंगे। यह जो विषय आपने यहां पर रखे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है । बड़ी गम्भीर बातें हैं जो ये बोल रहे हैं।

12.03.2018/1410/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 44 क्रमागत

उद्योग मंत्री क्रमागतः

एक व्यक्ति क्रशर लगाता है और क्रशर लगाने के साथ-साथ फिशिंग पौंड की परमिशन लेता है वहां मछली तो कोई पैदा होती नहीं लेकिन जो बड़े-बड़े पत्थर होते हैं उनको उठाता है और अपने काम में लगाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन यह जो फिशिंग पौंड की परमिशन है यह मत्स्य विभाग देता है। आपने पूछा है कि ऐसे कितने मामले हैं मेरे पास इसकी इंफोरमेशन नहीं है लेकिन मैं आपको पूरी की पूरी इंफोरमेशन दे दूंगा जो आप मांग रहे हैं। एक आपने पैनल्टी की बात की है। चलने वालों की पैनल्टी पूछ रहे हैं या वैसे इन जनरल पैनल्टी की बात की है --(व्यवधान)--यह मैं अलग से इंफोरमेशन दे दूंगा, यह मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्षः मुझे लगता है कि जितने प्रश्न उन्होंने पूछे हैं वे विस्तार से आप इनको लिखित भी भेज सकते हैं। श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी एक क्रशर लगाया हुआ है वह इल्लीगल है, रीवर बैड पर है। लोग प्रदूषित पानी पी रहे हैं। ढाई किलोमीटर रोड बिना फॉरैस्ट क्लीयरैंस के बना लिया है। पिछली सरकार में मैंने प्रश्न किया था तो फॉरैस्ट वालों ने लिख कर दिया कि हमने 10 हजार रुपये जुर्माना कर दिया है। सैंकड़ों वहां पर वृक्ष काटे गए। दस टायरी गाड़ी के ट्राले

चले हुए हैं, वह रोड था नहीं, एक जीप रोड पीछे मैंने गांव के लिए बनाया हुआ था उसका भी उन्होंने सत्यानाश कर दिया है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, क्या यह चक्की खड्ड से संबंधित है?

श्री बिक्रम सिंह जरयालः सर, यह देहर खड्ड से संबंधित है। ग्राम पंचायत जोलना और जोलना हमारे भटियात से जुड़ी हुई नहीं है।

अध्यक्षः यह जो प्रश्न है यह चक्की खड्ड का है।

12.03.2018/1410/SS-DC/2

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यही है कि थोड़ा इस पर भी कार्रवाई करें।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो चक्की खड्ड का है परन्तु जिन-जिन खड्डों पर कोई समस्या है वह बाद में मेरे साथ बैठकर डिस्कश कर लेना, उस सारी को ठीक करवा देंगे।

अध्यक्षः श्री राकेश सिंघा जी।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानकारी हासिल करना चाहूंगा कि 30 जनवरी को माइनिंग माफिया ने कानून को अपने हाथ में लेकर एक बहुत बड़ा ऑफैंस जो किया, that offence is covered under Section 3/7. उनके खिलाफ अटैक किया जो वहां विरोध कर रहे थे और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय, पूर्ण चंद शर्मा जिस पर आक्रमण हुआ था उनको टांडा हॉस्पिटल में मिले और आश्वासन दिया कि जिन्होंने घिनौनी कार्रवाई की है उनको गिरफ्तार जायेगा। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जहां पर यह हादसा हुआ है क्योंकि वह माइनिंग भी इल्लीगल है उसको जब्त करने के लिए सरकार ने कोई कार्रवाई की है?

अध्यक्षः यह कहां का मामला है?

श्री राकेश सिंघाः सर, यह चक्की खड्ड का है।

दूसरा, जो ऑफैंडर्ज़ थे उनको गिरफ्तार करने का कुछ काम किया है या नहीं?

उद्योग मंत्रीः माननीय सदस्य जिस बात के बारे में बोल रहे हैं चिन्ता कर रहे हैं उनके ध्यान में रहे कि वर्तमान सरकार ने एकदम ऐक्शन करते हुए जिन्होंने ऐसा किया था उनका क्रशर सील कर दिया है। वह बंद है। जहां तक आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, इस विषय में मेरे पास कोई लेटैस्ट जानकारी नहीं है लेकिन मुझे इतना पूरा पता है कि जो एस0पी0 कांगड़ा थे --(व्यवधान)-- मुख्य मंत्री जी तो जिसको चोट लगी थी उसका हाल-चाल पूछने के लिए गए थे। लेकिन जो आपने पूछा है हमारे विभाग ने उस पर एकदम कार्रवाई की थी। यह मंड में

12.03.2018/1410/SS-DC/3

चिन्तपुरनी स्टोन क्रशर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। विभाग ने इस पर पूरी कार्रवाई की है। जहां तक गिरफ्तारी का मामला है, गिरफ्तारी के मामले में मेरे पास सूचना नहीं है।

अध्यक्षः अंतिम सप्लीमेंटरी श्री राकेश पठानिया जी।

12.03.2018/1415/केएस/डीसी/1

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से जो स्पैसिफिक क्वैश्चन्ज़ पूछे, मुझे लगता है कि इनके पास ज्यादा इन्फोर्मेशन है लेकिन मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो फिशिंग पॉंड्ज के नाम से क्रशर चल रहे हैं, इन्हें बन्द करवाने का क्या आप कोई प्रावधान कर रहे हैं? दूसरे, आपके पास शायद सूचना नहीं है परन्तु मैं आपको दे रहा हूं। आज की डेट में वहां पर 80 करोड़ 71 लाख 20 हजार रुपये जुर्माने हुए हैं और यह केवल एक स्पैसिफिक एरिया के हैं अगर आप पूरे हिमाचल प्रदेश में ले कर जाएं तो यह बहुत बड़ी रकम बनेगी। ये सारी की सारी पिछली सरकार की आपको जो एक सौगात मिली है, इसको आप कैसे सम्भालने वाले हैं? तीसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जैसे विधान सभा की छुट्टियां पड़ेगी तो क्या आप और आपका विभाग मेरे साथ जाकर वहां पर साइट देखने का कष्ट करेंगें?

उद्योग मंत्रीः पठानिया जी, आपके साथ जाने का तो मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। वहां पर चुनाव में मेरी डियूटी लगती रही है। जो आपने पूछा तो हाई कोर्ट ने सी.डब्ल्यू.पी. नम्बर 7850/2010 दिनांकः 14.09-2017 को ऑर्डर जारी किए हैं जिसके अन्तर्गत 34 स्टोन क्रशरों को दोबारा फ्रैश नोटिस दिए जाने के बारे में आदेश हुए हैं। जब तक ये नोटिस फाइनल नहीं होते तब तक उनसे पैसा वसूला नहीं जा रहा है। आपने ठीक कहा कि यह हमारे लिए पिछली कांग्रेस सरकार की सौगात है। जुर्माने के बारे में जो आपने पूछा तो टोटल 120 स्टोन क्रशर्ज़ को नोटिस दिए जा चुके हैं और 87 स्टोन क्रशर्ज़ जिला कांगड़ा के हैं। जिला कांगड़ा में 8 स्टोन क्रशर्ज़ का जुर्माना जमा करवा दिया गया है। जो लेट हो रहा है वह केवल कोर्ट के कारण लेट होगा लेकिन फाइनल ऑर्डर होने तक हम उनसे जुर्माना ले लेंगें। दूसरे, जो आपने फिशिंग पॉंड्ज़ की बात की, इस बारे में विभाग ने जो बताया है उसके मुताबिक वर्तमान में तो किसी ने परमिशन नहीं ली है लेकिन जो आपने कहा कि पहले ऐसा-ऐसा हुआ है तो जो आप मेरा टूअर प्रोग्राम बना रहे हैं, हम इकट्ठा चलेंगें

12.03.2018/1415/केएस/डीसी/2

और इन्हीं छुट्टियों में चल पड़ेंगें और वहां देख लेंगें कि कहां-कहां ये पॉंड्ज़ हैं, कहां-कहां क्या-क्या हुआ है ताकि उससे हमारा भी ज्ञान बढ़े। आपको तो काफी ज्ञान है, आपने तो इसके ऊपर पी0एच0डी0 कर ली है । मैं आपके साथ चलूंगा और जो भी आपने कहा, हिमाचल प्रदेश के लिए यह बड़ी गम्भीर समस्या है। इसके समाधान के लिए आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगें और इसको ठीक करेंगें।

12.03.2018/1415/केएस/डीसी/3

प्रश्न संख्या-45

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है, मैं यह नहीं कहूंगा कि मंत्री जी इसके लिए दोषी हैं क्योंकि विभाग ने जो सूचना दी वही

सभा पटल पर रखी गई है। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो आपने सूचना रखी है, यह सही तस्वीर नहीं है। नैनादेवी के पास सलोहा पंचायत में कनफारा घाट से एक स्कीम बनी है जिसकी आधारशिला 6 अगस्त, 2012 को मैम्बर, पार्लियामैंट ने रखी थी और इसका काम 9.11.2012 को अवार्ड हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, उसके पांच टैंक बने और पांच में से क्योंकि जब स्कीम बन गई तो विभाग ने यह कहा कि सोर्स में पानी नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि लीन सीज़न में विभाग के लोग जब कोई स्कीम बनाने के लिए कोई प्रारूप तैयार करते हैं तो क्या यह नहीं देखा जाता कि वहां पर पानी है या नहीं है? ये पांच गांव हैं ।इन गांवों के लिए वहां से उठाऊ योजना बनी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कनफारा घाट है ,

12.3.2018/1420/av/hk/1

प्रश्न संख्या : 45-------- क्रमागत

यह ग्राम पंचायत स्लोहा है जो कि भाखड़ा के पास पड़ती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पांच टैंकों में डेढ़-दो साल से पानी नहीं आया। अब गर्मी का मौसम आ गया है इसलिए नैना देवी की स्कीम से मंदिर न्यास से पैसा देकर उस पांच नम्बर टैंक में सवा ईंच पानी डाला गया है। चार टैंकों में पानी नहीं है, मंत्री जी, इसकी वस्तुस्थिति यह है। यही स्कीम नहीं बल्कि ऐसी और भी स्कीमें हैं। जिला की ग्रीवैंसिस कमेटी में भी यह मसला लगभग चार बार उठ चुका है। हमारे झण्डुता निर्वाचन क्षेत्र की दो स्कीमें हैं और उन दो स्कीमों में पिछले 10-12 वर्षों से पानी ही नहीं आया। अब कहा जा रहा है कि उन स्कीमों को दोबारा से किसी और जगह से बनाना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र और कनफारा सूखा एरिया है। इस स्कीम पर लगभग 80-86 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और अगर इतना अधिक पैसा खर्च करके पानी न आए तो यह चिन्ता का विषय है। क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके इस ओर कोई कदम उठायेंगे?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, थोड़ा सा कनफ्यूज़न है। मेरे पास उपलब्ध सूचना के अुनसार जिला बिलासपुर में केवल बैहल-स्वाहण-री उठाऊ पेयजल योजना है। विभाग ने इसी योजना के बारे में बताया है। (---व्यवधान---)

श्री राम लाल ठाकुर : मंत्री जी, स्वाहण स्वारघाट से अगली पंचायत है और यह भाखड़ा से तीसरी पंचायत है जहां पर अभी तक पानी नहीं आया। नैना देवी से वहां के लिए पानी की सप्लाई दी गई है जिसके कारण अब वहां पर पानी की कमी आ जायेगी। नैना देवी से सवा ईंच पानी उठाया और टैंक नम्बर पांच में डाल दिया ताकि वहां के लोगों को गर्मियों में पानी मिल पाये। अतः मैं चाहूंगा कि विभाग इसकी सूचना भी दें या आप मंगवा लें।

12.3.2018/1420/av/hk/2

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : माननीय सदस्य, ऐसा नहीं है। हम किसी स्कीम के बारे में सूचना छिपाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन मेरे पास बैहल-स्वाहण-री उठाऊ पेयजल योजना के बारे में सूचना दी गई है। इस परियोजना की ए0ए0 एण्ड ई0एस0 25.9.2008 को हुई और यह 155 लाख रुपये की योजना है तथा इसकी पूर्ण करने की तिथि 16.2.2012 है। अब जो आपने यहां बताया उससे मुझे लगता है कि एक स्कीम यह है तथा इसके अलावा एक स्कीम और है; इस तरह से दो स्कीमें हो गई। मैं आपको मेरे पास उपलब्ध सूचना के बारे में अवगत करवाना चाहूंगा। यह योजना किस चुनाव क्षेत्र से सम्बंधित है, मुझे यह नहीं बताया गया है। यहां केवल बिलासपुर जिला के बारे में बताया गया है कि इसमें तीन पंचायतें पड़ती हैं। इस योजना को बनाते समय इसमें एक पानी का स्रोत लिया गया। दूसरे, केंद्रीय ग्राऊंड वाटर बोर्ड ने एक ट्यूब वैल बोर किया था। वहां पर जो ट्यूब वैल बोर किया गया था उससे उनकी रिपोर्ट के अनुसार 7.69 लीटर प्रति सेकिण्ड पानी निकलना बताया गया है। हमने जब उसको केलकुलेट किया तो सारे-का-सारा पानी 6,64,416 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनता है। हमने उस आधार पर उस स्कीम का काम वर्ष 2008 में आगे शुरू किया। मैंने जैसे पहले कहा कि दिनांक 16.2.2012 को स्कीम के काम को विधिवत रूप से पूरा कर

दिया गया। लेकिन जब स्कीम को पूरा किया गया तो जहां उन्होंने 6,64,416 लीटर पानी की बात कही था और

12.3.2018/1425/TCV/HK-1

प्रश्न संख्याः 45 क्रमागत्

माननीय सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य मंत्री.. जारी

दूसरा जो हमारा एक स्रोत था उससे हमें 29 हजार 40 लीटर पानी मिलना था। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो हमारा टयूबवैल वाला सोर्स था, उसमें भी पानी घट कर 3, 35,900 लीटर रह गया है। अब वर्तमान में वह पानी और घटकर 2 लाख 9 हजार लीटर ही रह गया है। मेरे पास जो सूचना है, उसके अनुसार इस स्कीम में पानी नीचे से उठाया गया है और जब यह पहली स्टेज़ पर पहुंचा तो उससे नीचे का जो एरिया है उनको तो पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना शुरू हो गया। वहां से जब पानी दूसरे सोर्स में डाला गया तब वह ग्रेविटी मैन में आया। इसके बाद इसको ग्रेविटी मैन से दूसरे सोर्स में डाला गया और वहां से भी पानी इक्ट्ठा किया गया। लेकिन आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि जो ग्रेविटी मैन वाली लाईन है, वह भी वर्ष 2015 से बंद पड़ी हुई है। यहां से ऊपर जो पानी उठाया गया है, वह नीचे वाले एरिया को दिया जा रहा है। जिस सोर्स पर हम काम कर रहे थे, वहां पानी सूख गया और हमने वहां पर 3 हैंड़पम्प लगा दिये। अब वहां से पानी ऊपर वाले एरिया में भी दिया जा रहा है। इसके अलावा जो वहां का प्रस्तावित एरिया था, वहां पर पानी की कमी को पूरा करने के लिए 4 हैंडपम्प और लगाये गये हैं। ये हैंडपम्प 2015 -2017 के बीच में लगाये गये हैं। इस तरह से इस क्षेत्र को 7 हैंड़पम्पों से पानी दिया जा रहा है। हम आपसे सहमत कि यह एक बहुत बड़ा लैप्स है। हम डेढ़-दो करोड़ रुपया खर्च कर पानी की स्कीमें बनाते हैं और फिर जिस मकसद को लेकर स्कीमें बनाई जाती है, उसका उद्देश्य तो यह होता है कि उस एरिया की प्रस्तावति आबादी, गांवों को पेयजल उपलब्ध करवांये। लेकिन अब एक ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है कि लम्बे अर्से से बारिश नहीं हुई है और बारिश न होने के कारण अनेकों परियोजनाएं सूखने के कगार पर है। मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है, वह मैंने आपके सम्मुख रख दी है।

जहां तक आपने दूसरी परियोजना के बारे में बात की है, मैं निश्चित तौर पर आपको पूरी सूचना उपलब्ध करवाऊंगा। यह भी हो सकता है कि इसमें कोई कमी रही हो।

12.3.2018/1425/TCV/HK-2

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने आपको सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आश्वास्त किया है फिर भी आप अंतिम सप्लीमैंटरी पूछिए।

श्री राम लाल ठाकुरः मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में ये बात लाना चाहूंगा कि विभाग अपनी नालायकी को छुपाने के लिए माननीय मंत्री जी से गलत बयानबाजी करवा रहा है और विधान सभा सत्र में विभाग द्वारा गलत सूचना दी जा रही है। जिस स्कीम की आप बात कर रहे हैं, वह स्कीम बहल से है। कीरतपुर की बहल पहली पंचायत है। वहां पर काफी अर्से पहले ये डीप बोर करवाया था लेकिन बाद में इस स्कीम का पानी 3 पंचायतों में ले जाने की योजना बनी। जो ऊपर वाली स्कीम है, उसका उद्घाटन चुनाव से डेढ़ महीना पहले हुआ था। आज न बहल गांव को पानी है और न ही कोडावाली, री, स्वाण और टरवाड़ पंचायत को पानी उपलब्ध हो रहा है। क्योंकि वहां पर फोरलेन की एक सुरंग निकल रही है, उसके कारण इन दोनों-तीनों पंचायतों के स्रोत ड्राई हो गये हैं और सारा पानी सुरंग से नीचे जा रहा है। मैंने स्वयं मौके पर जाकर, जब पिछली सरकार थी, ये 7 हैंड़पम्प कम्पनी वालों को बुलाकर, उनसे पैसा लेकर, यहां पर लगाये हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने उनमें मोटरें तक फिट नहीं की हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस स्कीम की आप बात कर रहे हैं, यह वह स्कीम हैं, जिसका पम्प -हाऊस भी सिंक हो गया है और अब उसका काम लगा है।

12-03-2018/1430/NS/YK/1

प्रश्न संख्याः 45.....क्रमागत।

दूसरी जगह से जो पानी उठाया जा रहा है, उस टैंक का काम भी पूरा हो गया है, मोटर भी फिट हो गई है लेकिन जब यह टैंक भरा तो मोटर और टैंक दोनों गोबिन्द सागर में चले गये। अब आप खुद ही सोचिये कि वहां पर यह कितना अच्छा काम हुआ होगा, क्योंकि यह सड़क से दूर था। इसलिए मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि डिपार्टमैंट जो सूचना आपको दे रहा है, वह बिल्कुल सही नहीं है। आप कृपा करके इन गलत सूचना देने वालों

को पूछिए। यह गलत सूचना मंत्री महोदय के माध्यम से क्यों दिलवायी जा रही है? दूसरा, जो मैंने आपको बताया है यह कनफारा डी.पी.एफ. का एरिया है और कनफारा एच0पी0 का एरिया भी है। यहां पर चमारड़ा हरिज़न बस्ती, बटेड़ गांव, टिब्बा और सलोआ हरिज़न बस्ती है, इनके लिए यह स्कीम बनी हुई है और इसके लिए पानी भी आया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये क्षेत्र प्रोन एरियाज़ हैं और वहां पर पहले कभी दिल्ली से प्लानिंग कमीश्न के चेयरमैन और अधिकारीगण आये थे, उन्होंने लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि श्री नैना देवी जी को पानी काला कुंड से उठाने के लिए दी थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब दूसरी स्कीम श्री नैना देवी जी को आ गई तो पिछले छः वर्षों से, जब से इस स्कीम का उद्घाटन हुआ है, एक बूंद पानी भी नहीं आया है। सारी स्कीम की मोटर्ज़ चोरी हो रही हैं और इस पर डिपार्टमैंट कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जब यह 10 करोड़ की स्कीम बनी है और उस एरिया में पानी नहीं है, इस पुरानी स्कीम को बन्द करने की क्या ज़रूरत महसूस हो रही है? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये सारा एरिया चंगर है और चंगर एरिया में पानी चंगर स्कीम का ही आता है। लेकिन भाखड़ा से ले करके जगाधखाना के एरिया तक जो गोबिन्द सागर के साथ लगती पहाड़ी है, वहां की स्कीमों का हाल खराब है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप व्यक्तिगत तौर पर जा करके इन स्कीमों को देंखे और जो आपको सूचना दी जा रही है वह गलत है। क्योंकि इन्होंने खुद गलतियां की हैं और उनको छिपाने के लिए आपको गलत सूचना दे रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आपके पास विषय आ गया है और आप उत्तर दें।

12-03-2018/1430/NS/YK/2

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, जो सूचना माननीय सदस्य जी दे रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर स्वयं जाऊंगा और यदि माननीय सदस्य के पास समय होगा तो आप भी चलें तथा वहां जा करके देखेंगे। आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार यानि भारतीय ज़नता पार्टी की सरकार किसी निर्दोष को दोषी बनाने की कोशिश नहीं करेगी और किसी दोषी को निर्दोष साबित करने की कोशिश नहीं करेगी। यहां दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। हम इसके लिए जल्दी ही कोशिश करेंगे। हमारा 17 मार्च से 25 तारीख का पीरियड अवकाश का है और मैं उस पीरियड के बीच में ही आपसे टाई-अप

कर लूंगा तथा मैं वहां पर विभाग के अधिकारियों को ले जाऊंगा। अगर सूचना गलत दी गई होगी तो उचित कार्रवाई की जायेगी।

12-03-2018/1430/NS/YK/3

Question No: 46

अध्यक्षः संबंधित प्रश्न का उत्तर आ गया है। माननीय राकेश सिंघा जी आप बोलिए।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन एजुकेशन करंट लिस्ट में है और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का लम्बे समय से विवाद चला है कि यह धर्मशाला में या देहरा में होगा। मेरा संकेत यह है कि कहीं यह तो नहीं कारण बन रहा है जिससे विश्वविद्यालय का स्तर और विश्वविद्यालय के अंदर जो अध्यापक और प्रोफैसर्ज़ हैं, वे इस विवाद के चलते हुए कहीं पीछे तो नहीं हट रहे हैं। हमें यह विवाद नहीं बनाना है। हम चाहते हैं कि यह सरकार इस विवाद को हमेशा के लिए सैटल करे। मैं समझता हूं कि एक विश्वविद्यालय चार स्थानों पर नहीं हो सकता है और न ही दो जगहों पर हो सकता है। Once and for final take a decision कि कहां पर यह विश्वविद्यालय हो, जिससे इसका स्तर नीचे न गिरे।

12.03.2018/1435/RKS/YK-1

प्रश्न संख्याः 46...जारी

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने उचित चिंता जताई है। इतना समय हो गया है लेकिन अभी तक हम सैंट्रल यूनिवर्सिटी को ज़मीन उपलबध नहीं करवा सके हैं। इसके लिए सैंट्रल गवर्नमैंट से दो कैम्पस तय हो गए हैं और ये कैम्पस धर्मशाला और देहरा में होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने देहरा की ज़मीन सैंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम कर दी है। इसमें फॉरैस्ट की क्लीयरैंसिज के लिए जो पैसा इत्यादि जमा करवाना था, वह भी जमा हो गया है। धर्मशाला, में ज़मीन तय कर दी है लेकिन वह ज़मीन अभी तक

ट्रांसफर नहीं हो पाई है। हम बहुत जल्दी दोनों स्थानों की ज़मीनें इस यूनिवर्सिटी को दे देंगे और इसका विधिवत् शिलान्यास भी इसी वर्ष के भीतर करेंगे।

श्री होशयार सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि धर्मशाला में कितने परसैंट यूनिवर्सिटी फंक्शन करेगी और देहरा में कितने परसैंट?

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक देहरा से संबंध रखते हैं लेकिन इसकी परसैंटेज अभी तय नहीं हुई है। जिस-जिस स्थान पर जितनी-जितनी ज़मीन होगी, यह ज़मीन की उपलब्धता पर ही तय होगा। यह यूनिवर्सिटी दोनों स्थानों पर बनेगी। मेरा सदन से निवेदन है कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी को मिले हुए कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन यह यूनिवर्सिटी अभी तक फंक्शन नहीं कर पा रही है। बाकी सब स्थानों में यूनिवर्सिटीज़ फंक्शन कर रही हैं। उनके कॉलेज प्रोपर चल रहे हैं। चाहे वे इंजीनियरिंग कॉलेज हों, मैडिकल कॉलेज हों, वैटरनरी व अन्य डिपार्टमैंट्स या स्कूल हों, वे सब प्रोपर चल रहे हैं। हम केवल मात्र इस विवाद में फंसे हुए हैं कि यह यूनिवर्सिटी देहरा में होगी या धर्मशाला में। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि यह यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला में ही बनेगी । इस यूनिवर्सिटी को बनने दिया जाए। जितना पोर्शन जहां आता है, उसमें जितनी ज़मीन उपलब्ध होगी, वह दे दी जाएगी। सैंट्रल यूनिवर्सिटी फंक्शन करे यह हम सबकी चिंता होनी चाहिए।

12.03.2018/1435/RKS/YK-2

<u>प्रश्न संख्याः47</u>

श्री इन्द्र सिहं(सरकारघाट)ः अध्यक्ष महोदय, इस योजना का शिलान्यास वर्ष 2012 को माननीय पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय धूमल साहब ने किया था। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पूर्व सरकार ने पिछले पांच सालों में इस योजना के लिए कुछ नहीं किया। इस खड्ड में बाढ़ आने की वजह से सैंकडों बीघा ज़मीन बह जाती है। जितनी भी पंचायतें इस खड्ड के किनारों के आस-पास आती हैं, वे बाढ़ के कारण बूरी तरह से प्रभावित होती हैं। मैं वर्तमान

सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इन्फ्लेशन के हिसाब से इसके लिए रिवाइज्ड डी.पी.आर. तैयार की है और इस डी.पी.आर को 62 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 160.88 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि सैंट्रल वाटर कमीशन की स्वीकृति कब तक अपेक्षित है? दूसरा, अगर सी.डब्ल्यू.सी. से रिपोर्ट जल्दी नहीं आती है तो पिछली सरकार द्वारा 21-22 स्थान ऐसे चिन्हित किए हैं, जहां बाढ़ के आने से जानमाल का खतरा बढ़ जाता है। क्या सरकार उन स्थानों में फ्लड प्रोटैक्शन का काम करवायेगी? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

12.03.2018/1440/बी0एस0/ए0जी0-1

प्रश्न संख्या 47 जारी.....

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, आदरणी सदस्य जी ने जो जानना चाहा है, यह निश्चित तौर पर गम्भीर बात है। 62.46 लाख रुपये से बनने वाली फ्लड मेनेजमैंट की एक योजना जो सरकाघाट से जाहू तक प्रस्तावित है। इस योजना के तटीयकरण से तीन चुनाव क्षेत्रों को इसका फायदा मिलेगा। माननीय सदस्य ने इसमें सैकड़ों बीघा कहा, मैं तो कहूंगा कि इससे हजारों बीघा भूमि बरबाद हो जाती है क्योंकि सीर खड्ड जब चलती है तो यह कई स्थानों पर अपना रास्ता बदल लेती है। हजारों बीघा भूमि इसकी चपेट में आ जाती है। लेकिन जैसे ऊना में बहुत सी भूमि फसल के काबिल बनी है। इसी प्रकार से इस योजना के पूर्ण होने पर भी हमें फायदा होगा। लेकिन यह सही है कि 2012 में इसका शिलान्यास रखा गया था। अगर 2012 में ही इस योजना का कार्य आरम्भ हो गया होता तो 62.46 लाख में यह योजना बन कर तैयार होती। लेकिन पांच साल इस फ्लड मेनेजमैंट की इस योजना को पीछे-पीछे धकेला गया। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि इस योजना के ऊपर लगभग 160 करोड़ से भी ज्यादा की राशि इसमें खर्च होने जा रही है। दोबारा से पूरा प्रोसेस हमारे को शुरू से ही करना पड़ रहा है । सब डीविजन लेवल से इसका दोबारा से सर्वे किया गया।

सारी योजना का प्राक्लन बदल करके तैयार किया गया। पुणे से टीम आई उसने इसका सर्वे किया, उसके बाद हमारा जो डायरेक्टर CWC शिमला में है, उसके बाद चंडीगढ़ में, अब योजना हमारी अंतिम चरण पर दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली में भी इसमें कुछ आब्जर्वेशन लगी थी और जो आब्जर्वेशन लगी थी, वह भी अब विभाग ने पूरी कर ली है। एक-दो बाकी बची हैं उनको एक-दो दिनों के अन्दर पूर्ण करने की तरफ बढ़ रह हैं। इस बरके अभी सम्भावित है, अभी मैं दिल्ली सरकार के बारे में नहीं कह सकता कि कब तक इसमें अनुमति मिलेगी। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस योजना के बारे में आदरणीय गडकरी जी को पत्र लिखा है, जो पत्र लिखा है उस पत्र के बारे में आदरणीय गटकरी जी, जिनके पास फ्लड मेनेजमैंट विभाग भी है, उन्होंने इस योजना को अपनी प्राथमिकता दी है। उस प्राथमिकता के आधार पर ऐसा सम्भावित है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च, 2018 से पहले-पहले अगर यह हमारी योजना फंडिग के लिए लग जाए तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम कोशिश कर रहे हैं इनमें तीन विधासभा चुनाव क्षेत्रों को जिसमें भौंरज विधान सभा चुनाव क्षेत्र है, सरकाघाट विधान

12.03.2018/1440/बी0एस0/ए0जी0-2

सभा चुनाव क्षेत्र है और थोड़ा सा हिस्सा धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र का आता है। हम प्रयासरत है कि इसको भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान की जाए।

12.03.2018/1440/बी0एस0/ए0जी0-3

प्रश्न संख्याः 49

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है उसमें यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर 4924 पम्प हाऊस हैं और उसमें से पम्प ऑपरेटर अभी जो विभाग के पास स्वीकृत पद हैं वह 3165 हैं। उसमें से भी 674 खाली हैं और हिमाचल प्रदेश के अन्दर 2433 पम्प ऑपरेटरों के पद खाली पड़े हैं। इन सभी पम्प हाऊस को चलाने वाले बेलदार हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर बहुत सारी स्कीमें आऊट सोर्स की थीं। क्या सरकार जो स्कीमें आऊट सोर्स की हैं, आगे भी उन्हें आऊट सोर्स करेगी? जिन ठेकेदारों को आऊट सोर्स की

है उन्होंने बेलदार वहां लगाए हैं। कोई भी टैक्निकल आदमी वहां नहीं है। इस कारण से बहुत सारी मशीनरीज आई0पी0एच0 विभाग की खराब हो रही है और बहुत सारी लिफ्टें आई0पी0एच0 विभाग की बंद हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है।

12.3.2018/1445/DT/AG-1

प्रश्न संख्याः 49...जारी

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस प्रश्न की जानकारी माननीय सदस्य जी ने जानना चाही है। उत्तर के (क) भाग में कहा है कि ' इन मोटरों और इन स्कीमों को हम पांच केटेगरी में चला रहे हैं। एक, जो विभाग में कार्यरत पंप ऑपरेटर हैं। दूसरा, पैरा पंप ऑपरेटर हैं। तीसरा, जो पंप अटैंडेट हैं। चौथा, जो हैलपर व बेलदार हैं। पांचवा, जो हमने बुहत ज्यादा स्कीमों को आउटसोर्स कर रखा है। जैसे माननीय सदस्य जी ने चितां जाहिर की है और अब विभाग के अन्दर एक ऐसी स्थिति है कि हमारा जो डाईंग कैडर है उस में 17, 951 पद डाइंग कैडर के हैं। जो रिटायर होता है, उसके साथ ही पद चला जाता है। हम ऐसी स्थति में पहुंच चुके है। अध्यक्ष जी कोई भी योजना बनती है,जितनी भी हमारी उठाऊ पेयजल परियोजनाएं हैं, उठाऊ सिंचाई पारियोजनाएं हैं, इनके पंप हाउसिज़ ऐसी जगह हैं या तो वहां पर शमाशान घाट है या ऐसी जगह है जहां रात को अकेला आदमी नहीं रहा सकता है। क्योकि पंप ऑपरेटर, अटेंडैंट और चौकीदार के न होने से वे स्कीमें बंद हो गई हैं। स्कीमें बंद होने से वहां पर बहुत चीजों की चोरियां हो रही हैं। मोटर और पंपों को चोर के ले गए हैं। यहां तक जो अन्दर वायरिंग की है उस को भी चोर उखाड़ कर ले गए। दूसरा, यह है कि जिन स्कीमों को हम आउटसोर्स के माध्यम से ठकेदारों को चलाने के लिए दिया है, उसमें उन्होंने अनस्किलड लोग रखे हैं। उनको पता नहीं है कि किस वोल्टेज में मोटर चलना चाहिए। वे बटन दबाते हैं और वॉल्टेज का ज्ञान न होने से मोटरों की कैपेसीटी खत्म कर दी है। मैं माननीय सदस्य जी को यह भी बताना चाहूंगा कि यदि हमारी राइजिंग मेन का डाया छः इंच का है तो उस प्रस्तावित

स्कीम का डिस्चार्ज पानी छः इंच ही ऊपर पहुंचना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैंने अनेकों स्कीमों का स्वयं मुआयना किया है। मुआयना करने पर मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि नीचे मोटर चली हुई है, पंप चला हुआ है, बिजली का मीटर भी घुम रहा है और ऊपर पानी

12.3.2018/1445/DT/AG-2

छः इंच की जगह मात्र एक इंच या डेढ़ इंच ही पहुंच रहा है। जो ऊपर की स्टेज है, वहां से लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाना है, उन को पानी नहीं मिल रहा है। वहां पर हाहाकार है। लेकिन बिजली का बिल 5सौ करोड़ रुपये पहुंच रहा है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। ऐसा नहीं की यह हमारी गलती से है, यह जो आज उधर चले गये, उनकी गलती से है। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्कता है। मैं एक स्कीम के बारे में उदाहरण के रूप में कहना चाहुंगा। लग्वाल्टी-बमसन एक आउटसोर्स की स्कीम थी। मैने पुछा कितने में आउटसोर्स हुई।

12.03.2018/1450/SLS-DC-1

प्रश्न संख्या : 49 ...जारी

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री... जारी

यह स्कीम एक करोड़ रुपये में आऊटसोर्स हुई। मैंने पूछा कि कितने लोग रखे तो कहा गया कि 26 लोग रखे गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम एक करोड़ की स्कीम के लिए 26 लोग रख रहे हैं जो कि एग्रीमैंट में है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो वहां पर 15-16 से ज्यादा लोग नहीं हैं। दूसरे, जिन स्कीमों को दिया गया, उनके पंप बैठ गए; उनकी मोटरें बैठ गईं। अब हमारे सामने एक बहुत लंबा सूखे का मौसम खड़ा है। अगर इन मोटरों को, इन पंपों को ठीक करने के लिए हमें राशि नहीं मिलेगी तो हमारे लिए मुश्किल होगी ही। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए कि जो हमारी मैन पॉवर है, उसे बढ़ाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग में मशीनरी आ चुकी है। लोक निर्माण विभाग में मिक्चर है, लोडर है और एक्सक्वेटर हैं। लेकिन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में जो उठाऊ जल परियोजना है, वह तो आदमी से ही चलेगी। उसको पंप ऑप्रेटर ही चलाएगा और पाईप को फीटर ही फिट करेगा। इसलिए मैं निश्चित तौर पर आपसे सहमत हूं कि हमारे यहां पर मैन पॉवर की बहुत ज्यादा कमी है। **इस कमी को पूरा करने के लिए विभाग इस पर विचार कर रहा है और जो भी उचित कार्रवाई होगी, माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन से हम वह कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे।**

अध्यक्ष : वैसे तो मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है, पर, माननीय मंत्री जी, मेरा भी यही कहना है कि पानी की स्कीमों की दशा को सुधारना बहुत ज़रूरी है।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आपने जो स्कीमें आऊटसोर्स की हैं, उनके बारे में अगर विभाग से बात करें तो वह बोलते हैं कि आऊटसोर्स हैं और अगर आऊटसोर्स वालों से बात करें तो वह बोलते हैं कि मोटरें खराब हैं, इसलिए नहीं चल सकती। मेरी आपसे विनती है कि विभाग इस कार्य को अपने हाथ में ले। विभाग से तो बात की जा सकती है लेकिन ठेकेदारों से बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है; वह हमेशा विभाग के ऊपर ही इसकी सारी ज़िम्मेवारी डालते हैं। दूसरे, जो आपके पंप ऑप्रेटर्ज़ हैं, अभी उनके 2491 पद खाली हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय कुल 4924 पंप हाऊस हैं। इसलिए इन खाली पदों को भरने की सरकार

कब तक कोशिश करेगी, क्योंकि जब तक यह पद नहीं भरे जाएंगे तब तक यह पानी की सभी स्कीमें सुचारू रूप से नहीं चलेंगी। यह दो बड़े इसु हैं जिनमें एक आऊटसोर्सिंग का है और दूसरा पंप ऑप्रेटर्ज़ का है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, पहली सप्लीमैंटरी में माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जो स्कीमें आऊटसोर्सिंग करके दी हुई हैं उन स्कीमों से जब उपभोक्ता को पानी नहीं मिलता तो वह जे.ई. और एस.डी.ओ. को फोन करता है। जे.ई. और एस.डी.ओ. कहते हैं कि हमने तो आऊटसोर्स करके स्कीम फलां ठेकेदार को दी हुई

है। फिर ठेकेदार कहता है कि मोटर खराब है या पंप खराब है। अध्यक्ष जी, इस मामले में भी हमारे उस ओर के मित्रों ने एक नई शुरुआत की है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके नफ़ा-नुकसान विभाग के इंजीनियर्ज़ को, अधिकारियों को और मंत्री को देखने चाहिए कि हम जो यह फ़ैसला ले रहे हैं, क्या यह जनहित और प्रदेशहित में है? कहीं यह फ़ैसला ऐसा तो नहीं है कि यह हमारे गले पड़ जाए। **इसलिए मैंने कहा है कि इस फ़ैसले पर भी हम विचार कर रहे हैं। दूसरी बात आपने रिक्तियों को भरने की कही है। निश्चित तौर पर जो भी वैस्ट पॉसिबल होगा, हम कोशिश करेंगे कि यह रिक्तियां भरी जाएं।** अभी तो हमारे पास अनेकों ऐसी स्कीमें हैं जो निर्माणाधीन हैं। अगर उन स्कीमों को भी जोड़ दिया जाए तो उन्हें चलाने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता रहेगी। अब तो ग्रैविटी वाली स्कीमें समाप्त हो रही हैं, उनका प्रचलन ही अब खत्म है। अब तो जो भी स्कीमें बनेंगी वह उठाऊ पेयजल योजनाएं या उठाऊ सिंचाई योजनाएं ही बनेंगी। इसलिए जो उठाऊ पेयजल या उठाऊ सिंचाई योजना बनेगी, उसमें पंप ऑप्रेटर लगेंगे ही लगेंगे। वहां पर पंप हाऊस पर चौकीदार लगेंगे ही और डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम पर भी कर्मचारी लगेंगे ही, तभी जाकर उन स्कीमों का औचित्य होगा। अगर हम उनको नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसी कारण से आज हमारी अनेकों स्कीमें बंद पड़ी हैं। **इस इस पर भी विभाग विचार कर रहा है।**

12/03/2018/1455/RG/DC/1

प्रश्न सं. 49--क्रमागत

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया है और जो स्कीमें अभी बन रही हैं, उनके बारे में इन्होंने ज्यादा चिन्ता ज़ाहिर की। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे ही चुनाव क्षेत्र में सात स्कीमें ऐसी हैं जिनके पम्प जल गए हैं। सूखा पड़ा हुआ है। अब विभाग यह कह रहा है कि हमारे पास टैनीकल स्टाफ नहीं है और जो ऑऊटसोर्स पर रखे गए हैं वे नॉन-टैक्नीकल लोग हैं, ठेकेदार टेलीफोन नहीं सुनता और अध्यक्ष महोदय, हमारा हाल यह है कि लोग रात को

11.30-12.00 बजे जब उनको चुस्ती है, तब वे फोन करते हैं कि पानी नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन यह है कि इस बारे में सोचा जाए क्योंकि आने वाली गर्मियों में इस मसले को सुलझाना बहुत आवश्यक है। आने वाली गर्मियां कैसे निकालेंगे? इसके लिए चाहे आप टैम्पोरेरी पम्प ऑपरेटर्ज रखें, लेकिन यदि आप टैक्नीकल स्टाफ रखेंगे, तब इन गर्मियों में पानी का इन्तज़ाम हो सकता है।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने इस पर बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, लेकिन फिर भी ठाकुर साहब ने प्रश्न पूछा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर विभाग के साथ आदरणीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में इस सूखे को लेकर दो बार चिन्तन बैठक हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिए हैं और उनके अनुरूप में हमें कुछ राशि कुछ स्कीमों को पूरा करने के लिए भी दी गई है। इसके साथ-साथ विभाग अपने तौर पर और हम भी इससे चिन्तित हैं। यहां प्रश्न इधर या उधर का नहीं है बल्कि यहां पूरे प्रदेश का प्रश्न है कि आने वाली गंभीर समस्या जो हमारे सामने खड़ी हो रही है, इसका किस प्रकार से समाधान कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इस पर संवेदनशील है और हम आने समय में इस पर यथासंभव प्रयास करेंगे। इस माननीय सदन में जो चुने हुए प्रतिनिधि, इसके साथ-साथ पंचायत स्तर के चुने हुए प्रतिनिधियों और आम-आदमी का भी सहयोग इसमें वांछित है क्योंकि सहयोग के बिना यह काम नहीं हो सकता। इसलिए यह हमारा सांझा दायित्व है। यह किसी एक पक्ष का दायित्व नहीं है इसलिए सबका सहयोग मिलना अति-आवश्यक है और मैं आपसे भी सहयोग की प्रार्थना करता हूं।

12/03/2018/1455/RG/DC/2

श्री सुख राम : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी स्कीमें बनाने में 10-10 या 15-15 साल लग जाते हैं। हम जब उसको ऑऊटसोर्स करते हैं, उसके छः महीने में ही स्कीम खराब हो जाती है जबकि वहां के लोगों ने सपना लिया होता है कि जब स्कीम तैयार होगी, तो हमें पानी मिलेगा। क्या सरकार कोई ऐसा नीतिगत फैसला करेगी कि जब कोई सिंचाई या पीने-के-पानी की लिफ्ट की स्कीम स्वीकृत हो, तो उसके साथ ही पम्प ऑपरेटर्ज या

अटेन्डेंट्ज के पद भी स्वीकृत हों? ताकि स्कीम चलने के साथ ही पम्प ऑपरेटर या अटेन्डेंट मिले और स्कीम प्रौपर तरीके से चले।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो माननीय सदस्य का बहुत अच्छा सुझाव है कि जब कोई स्कीम बने, तो उसी समय उसके स्टाफ का भी प्रावधान रखा जाए। वैसे तो हमने भी कहा है कि भविष्य में बनने वाली जितनी भी स्कीम्ज हैं, जब उनका प्राक्कलन तैयार किया जाए, तो उसमें एक अमाउन्ट उसको चलाने का भी रखा जाए। कुछ स्कीमों को हमने पांच साल के लिए कहा कि जो बनाएगा, वह पांच साल इनको चलाएगा। ऐसा भी शुरू किया, लेकिन उस पर भी मैंने एक स्टडी की है। इसमें क्या हो रहा है कि जहां पांच साल तक उनको चलाने का अमाउन्ट दिया जा रहा है, हम उनको जितना पांच साल का अमाउन्ट दे रहे हैं, उसकी तुलना अगर हम अपने द्वारा वहां पर रखे गए स्टाफ से करें, तो हमने जो अपना स्टाफ वहां रखा है, उसमें पैसा कम लगेगा और उनके द्वारा ज्यादा लगेगा और वैसे भी जो स्कीम नई होती है, उसमें वैसे भी पहले पांच सालों तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने की गुंजाइश नहीं होती। हां, इतना जरूर है कि यदि कोई बीस वर्षों के लिए मानता है, तब यह हो सकता है। **अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव श्री सुख राम जी ने दिया है, विभाग निश्चित तौर पर इस पर विचार करेगा।**

12/03/2018/1500/MS/HK/1

प्रश्न संख्याः 49 क्रमागत----

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो पिछली सरकार ने अंतिम दिनों में जाते-जाते जल-रक्षकों की नियुक्तियां शुरू की थीं और उसके लिए सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के एस0डी0ओ0 को नोडल ऑफिसर बनाया था क्या उन सूचियों को इम्प्लीमैंट किया जा रहा है? इसके अलावा, जो ये आउट-सोर्स पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं क्योंकि हम जिस भी गांव में जाते हैं वहां पर 5-6 लड़के मिल ही जाते हैं जो हमें बताते हैं कि पिछले 4 महीने, 8 महीने या किसी को 10 महीने के पैसे फलां ठेकेदार ने नहीं दिए हैं। इस तरह एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बहुत हो

रही है। तो इस आउट-सोर्सिंग को जल्दी-से-जल्दी बन्द करने का प्रस्ताव क्या सरकार रख रही है?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का आप लिखित में उत्तर दे दीजिएगा।

प्रश्न काल समाप्त

12/03/2018/1500/MS/HK/2

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय मान्य सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस मान्य सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जोकि इस प्रकार हैः-

सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2018 (1)शासकीय/विधायी कार्य।
(2)बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018-2019- सामान्य चर्चा।

मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2018 (1)शासकीय/विधायी कार्य।
(2)बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018-2019- सामान्य चर्चा।

बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2018 (1)शासकीय/विधायी कार्य।
(2)बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018-

2019- सामान्य चर्चा।

वीरवार, दिनांक 15 मार्च, 2018 (1)शासकीय/विधायी कार्य।

(2)बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018-2019- सामान्य चर्चा।

शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2018 (1)शासकीय/विधायी कार्य।

(2)बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018-2019- सामान्य चर्चा एवं चर्चा का समापन।

12/03/2018/1500/MS/HK/3

सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को मनोनीत करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

Industries Minister: Hon'ble Speaker, Sir, with your permission, I move the following resolution which is listed against my name in today's business:-

"That in pursuance of the provision contained under Section 16 (1)(j) of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015), the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the Member of the Board of Governors of Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur for a period of three years from the date of nomination."

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "That in pursuance of the provision contained under Section 16 (1)(j) of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015), the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two

members from amongst themselves to serve as the Member of the Board of Governors of Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur for a period of three years from the date of nomination."

तो प्रश्न यह है कि "That in pursuance of the provision contained under Section 16 (1)(j) of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015), the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do

12/03/2018/1500/MS/HK/4

proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the Member of the Board of Governors of Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur for a period of three years from the date of nomination."

(प्रस्ताव स्वीकार)

12.03.2018/1505/जेके/एचके/1

अध्यक्षः अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता परिषद् में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों को मनोनीत करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश सहकारी सभायें अधिनियम, 1968 (वर्ष 1969 का अधिनियम संख्या-3) की धारा 98(1)(4) के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य, स्वयं अपने में से, जिस प्रकार वे चाहें या जिस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, तीन सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यवाही करें, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य

सहकारिता परिषद् में, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त अधिनियम व उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, बतौर सदस्य, सेवा कर सकें, के मनोनयन हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश सहकारी सभायें अधिनियम, 1968 (वर्ष 1969 का अधिनियम संख्या-3) की धारा 98(1)(4) के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य, स्वयं अपने में से, जिस प्रकार वे चाहें या जिस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, तीन सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यवाही करें, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता परिषद् में, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त अधिनियम व उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, बतौर सदस्य, सेवा कर सकें, के मनोनयन हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश सहकारी सभायें अधिनियम, 1968 (वर्ष 1969 का अधिनियम संख्या-3) की धारा 98(1)(4) के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य, स्वयं अपने में से, जिस प्रकार वे चाहें या जिस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, तीन सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यवाही करें, जो

12.03.2018/1505/जेके/एचके/2

कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता परिषद् में, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त अधिनियम व उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, बतौर सदस्य, सेवा कर सकें, के मनोनयन हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

प्रस्ताव स्वीकार।

12.03.2018/1505/जेके/एचके/3

बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018-19 पर समान्य चर्चा

अध्यक्षः आज से वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों/वार्षिक वित्तीय विवरण पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ हो रही है तथा इसका समापन 16 मार्च, 2018 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उत्तर के साथ होगा। कार्य सलाहाकार समिति की अनुशंसा के अनुरूप कांग्रेस विधायक दल के नेता को 45 मिनट तथा अन्य सदस्यों को अधिकतम 15 मिनट का समय सुनिश्चित किया गया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन रहेगा कि वे अपना-अपना भाषण बजट तक ही सीमित रख कर, निर्धारित अवधि के भीतर समाप्त करें।

अब सर्वप्रथम मैं कांग्रैस विधायक दल के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को चर्चा आरम्भ करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी ने 9 मार्च, 2018 को जो बजट प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किए उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इनका यह पहला बजट था। आपने मुझे समय दिया मैं आपका भी आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा मुझे ऊंचाइयों पर देख हैरान है कुछ लोग।

12.03.2018/1510/SS-YK/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री क्रमागतः

अध्यक्ष महोदय, ये कौन लोग हैं? हम तो सिर्फ इतना जानते हैंः-

"शोहरत की बुलन्दी भी इक पल का तमाशा है,
जिस साख पर बैठे हो वह टूट भी सकती है।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने पौने तीन घंटे भाषण दिया, हमने बड़े संयम और अनुशासन से सुना। अब सत्तापक्ष से भी कहें कि ज़रा संयम/धैर्य रखें। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने 84 पन्नों का दस्तावेज़ यहां प्रस्तुत किया। आपकी भाषा में - बिना रूके, बिना थमे, बिना पानी पिये पौने तीन घंटे भाषण हुआ। हमने भी जानने की कोशिश की कि किस बात के लिए मुख्य मंत्री जी अपनी पीठ थपथा रहे हैं

और शुरूआत में ही इन्होंने कहा कि बी0जे0पी0 का जो नेतृत्व है उसके दिल में हिमाचल के प्रति बहुत स्थान है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल तो कांग्रेस नेतृत्व की बदौलत ही वजूद में आया है। यह कांग्रेस की लीडरशिप थी जिसकी बदौलत हिमाचल बना। जब आप लोग 'स्टेट हुड मारो ठूड' के नारे लगाते थे तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की वजह से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसलिए बेहतर रहता कि आप इस बात का उल्लेख भी कर देते। पहला बजट था, हमें बहुत उम्मीदें थीं कि आप प्रदेश को कोई दिशा देंगे। कोई इनोवेशन लायेंगे। कोई नयापन लायेंगे। लेकिन मुख्य मंत्री जी प्रदेश की अफसरशाही ने आपको पूरी तरह ठग दिया है। उन्होंने आपको एक विजनरी मुख्य मंत्री बनने का जो तगमा लगना था, उससे आपको पहले ही चूक करवा दी है। आपसे भी यहां अनाउंसमैंट करवा दी कि हम कर्ज़े से सरकार चलायेंगे। आपने यहां ऐलान कर दिया कि हम भी 28 परसेंट कर्ज़े लेंगे। रिसोर्स जनरेशन की आपने कोई योजना नहीं बनाई। इंटरस्टेट डिस्प्यूट का आपने इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। आपने स्टेट के लिए लम्बी अवधि की कोई प्लानिंग इस बजट में इंगित नहीं की। कोई रोडमैप आप इसमें दिखा नहीं सके और मुख्य मंत्री जी, हम तो आपको यही कहेंगे कि:-

12.03.2018/1510/SS-YK/2

"तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं,
कमाल है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं;
मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं,
मैं इन नज़ारों का अन्धा तमाशबीन भी नहीं।"

और गपोड़शंख या शेखचिल्ली बन के काम नहीं बनेगा, अध्यक्ष महोदय। कर्ज़े की बात है। आपने अपने भाषण में कर्ज़ों की दुहाई दी और हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आपके बजट के भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्ज़ वही लोग हैं जो हमारे हुआ करते थे। उन्हीं लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी। उन्होंने ही पूरी पटकथा तैयार कर दी। कोई एक-आध हास्य कलाकार बदला हो तो मैं कह नहीं सकता। अन्यथा वही लोग हैं और आपने कहा कि कर्ज़ लेकर घी पीने की नीति पर कांग्रेस चल रही थी। आपने यह आरोप कांग्रेस पर लगाया। आप पहले तो खुद बताएं कि आपने इस बजट में क्या आर्थिक प्रबन्धन किया है? आप तो दो महीने

तबादलों और जश्न में मशरूफ रहे और मुझे लगता है कि आपको शायद बजट बनाने या पढ़ने का मौका नहीं मिला। इसलिए आपने साफ तौर पर कह दिया कि कर्ज़ों पर सरकार चलेगी। केन्द्र की रियायतों पर सरकार चलेगी। साफ है कि आप बहुत भारी-भरकम लोन लेने वाले हैं, इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते। आपने कहा कि कांग्रेस, वीरभद्र सिंह सरकार ने कर्ज़ लिया।

12.03.2018/1515/केएस/वाईके/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी----

आप हमें बताएं कि कर्ज की सीमा का क्या किसी भी वित्तीय वर्ष में एक भी बार उल्लंघन हुआ? क्या वे उन सीमाओं के अंदर नहीं लिए गए? क्या इस दौरान कभी हिमाचल की ट्रेज़री बन्द हुई? आप भी जानते हैं कि पिछली दफ़ा आपकी सरकार थी, आप मुख्य मंत्री नहीं थे लेकिन उस वक्त के मुख्य मंत्री जी ने सरकार को रिपीट करने के लिए पंजाब पे कमेटी की सिफारिशें हिमाचल में लागू कर दी। आप वह पैसा दे कर नहीं गए। वह सारा पैसा माननीय वीरभद्र सिंह जी ने आ कर चुकता किया था। भारी भरकम पैसा उसमें इन्वॉल्व था और अब आपने हिसाब कर दिया कि बजट का जो गैप था वह आप भी कर्जे से ही पूरा करेंगें। आपने दिसम्बर तक के कर्जों की बात तो कर दी परन्तु कम से कम अपने दो महीनों के कर्जों की बात भी कर देनी थी कि दो महीनों में आपने दो हजार, 2200 करोड़ का कर्जा ले लिया और अगर 60 महीने हैं तो क्या आप 60 करोड़ का कर्ज़ा लेंगें? आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 247 परसेंट ज्यादा कर्जा लिया। लिखने में और कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि कांग्रेस ने 247 परसेंट कर्जा लिया लेकिन मुख्य मंत्री जी मैं आज आपको इस माननीय सदन में कहना चाहता हूं कि पांच वर्ष बाद जब आप इसी कुर्सी पर बैठे होंगे, आप पांच सौ परसेंट ज्यादा कर्जा ले कर यहां से जा रहे होंगें। आपकी प्रजेक्शन बता रही है । आप कहते हैं कि धूमल जी ने 28 हजार करोड़ तक पहुंचा दिया, आप कहते हैं कि वीरभद्र सिंह जी ने 46 हजार करोड़ तक पहुंचा दिया लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आप 75 हजार करोड़ तक पहुंचाकर जाएंगें और ये प्रजैक्शन्ज़ हैं जो आपने बजट में दी हैं, जो

साफ तौर पर नज़र आ रहा है इसलिए इन बातों पर ज्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जो प्रोड्यूसर और डायरैक्टर आपके हैं वे हमारे भी थे। इसी तर्ज़ पर आपको बता रहे हैं कि आप कहां पहुंचेंगें । यह कह दिया कि एन.डी.ए. ने 28,552 करोड़ दिया, यू.पी.ए. ने 46, 793 करोड़ दिया तो आपको भी मालूम है कि फंडिंग पैटर्न बदला है।

मुख्य मंत्रीः मुकेश जी, आपने फीगर्ज़ उलटे पढ़ दिए।

12.03.2018/1515/केएस/वाईके/2

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः मुख्य मंत्री जी, आपने कहा कि 46,700 करोड़ मोदी जी ने दिया। (व्यवधान)

अध्यक्षः कृपया बाकी लोग बोलिए मत।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः फीगर्ज़ बिल्कुल सही है आप कहते हैं कि आपकी सरकार ने 46,793 करोड़ दिया । पहले प्लानिंग कमिशन था उसकी जगह नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का पैटर्न बदल गया और पहले योजनाओं के लिए अलग-अलग फंडिंग आती थी। हर योजना की अलग-अलग फंडिंग आती रहती थी वह सारी रोक कर एक जगह इकट्ठी करके दे दी। उन्होंने जब सारा पैसा एक जगह इकट्ठा करके दे दिया तो इसमें क्या है? आज हम कहते हैं कि स्वां चैनलाइजेशन का पैसा नहीं आ रहा है। 500 करोड़ नहीं आ रहा है, वे कहते हैं कि स्टेट किटी से ले लो। आपके ऑफिसर कहते हैं कि हम नहीं देंगें, आप दिल्ली से लाओ। उन्होंने तो एक बार कह दिया कि सारा पैसा इकट्ठा करके हमने हिमाचल को एक मुश्त दे दिया । मुख्य मंत्री जी, आप लगातार दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। ट्रिब्यून अख़बार में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखकर आया कि आप बेल आऊट पैकेज़ ला रहे हैं। आप बताएं कि आपके बेल आउट पैकेज़ की बात कहां तक पहुंची है? क्या आप 50 हजार करोड़ रुपये ला रहे हैं? मुझे तो लगता है कि यह चुनावों तक की बात थी और जब वोट लेने थे तो कहा जा रहा था कि हिमाचल को सब कुछ देंगें और आज दिल्ली की भी प्राथमिकता बदल गई। आप 10 बार दिल्ली जा कर आ गए लेकिन आपने बजट के अंदर इस बात का एक बार भी खुलासा नहीं किया कि आपको क्या मिलने वाला है। रोज़ हम आपका फोटो देखते हैं दिल्ली में किसी न किसी के साथ बुके लिए हुए बड़ी

खूबसूरत अदा में फ़ोटो आती है। बता देते कि हिमाचल प्रदेश को क्या ये पैसा मिलने वाला है? मुख्य मंत्री जी, दिल्ली सरकार का यह अन्तिम साल चल रहा है। अगर जुलाई, अगस्त तक आप कुछ नहीं ला सके तो फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर जय राम जी की हो जाएगी। यह मैं आपको बता देता हूं। इसलिए जो लाना है, जुलाई, अगस्त से पहले ले कर आ जाएं।

12.3.2018/1520/av/ag/1

(---व्यवधान--)

अध्यक्ष महोदय, इनके यहां पर जो नये सदस्य आए हैं आप उनको बताएं क्योंकि हमने मुख्य मंत्री जी को बड़े संयम से सुना है। आपने भी भाषण देने हैं और आपकी भी स्पीचिज होनी हैं, इसलिए आप अभी संयम से सुनिए। चुनाव से पहले नौकरियों के बहुत सारे सपने दिखाये गये, उस दौरान बड़ी-बड़ी बातें कही गईं। इन्होंने पूरे हिमाचल का यूथ अपने पीछे लगा दिया कि हम नौकरियां देंगे और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का था। 'प्रदेश में युवाओं पर बेरोजगारी की मार और अबकी बार भाजपा सरकार'; इस तरह से युवाओं के साथ बहुत बड़े-बड़े दावे किए गए। मगर आपने अपने पहले ही बजट में हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा कर दिया। आपने हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा फरेब किया है। आपने गवर्नमैंट सैक्टर में नौकरियां क्रियेट नहीं की है, आपका पूरा दस्तावेज गवर्नमैंट नौकरियों को लेकर के साइलैंट है। इसमें ब्युरोक्रेसी ने बड़ी चुस्ती से एक अक्षर 'फंक्शनल पोस्ट' का डाला दिया लेकिन आप सरकारी नौकरियों पर पूरी तरह से साइलैंट हो गये। आपने हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को पूरी तरह से प्राइवेट सैक्टर में छोड़ दिया। मुख्य मंत्री जी, आपके क्या कहने? आप हिमाचल के 18 से 35 साल के युवाओं को अब बजट में यह कह रहे हैं कि दुकानें खोलो, आप निजी व्यवसाय करो; मैं मदद करूंगा। क्या आप अब हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से दुकानें लगवाओगे? आपने जो नीतियां दी हैं उसमें मुख्य मंत्री युवा आजीविका योजना, मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना, विद्यार्थी वन मित्र योजना; आपने 18 से 35 साल तक के बेरोजगार युवाओं को इस ढंग से छल दिया है कि अब आप उनसे दुकानें खुलवाओगे। सरकारी

नौकरियों का वादा करके आपने यह बहुत बड़ा फरेब किया है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कौशल विकास भत्ता हमारी सरकार के कार्यकाल में बखूबी चल रहा था। एशियन डैवल्पमैंट प्रोजैक्ट भी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय आ गया था

12.3.2018/1520/av/ag/2

और उसमें 100 करोड़ रुपये की हर साल फंडिंग हो रही थी। उसमें से डेढ़ लाख लोगों को कौशल विकास भत्ता दिया जा चुका है। आपने यह तो मैंशन कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 21 हजार लोगों को बेरोजगार भत्ता दिया लेकिन आपने यह भी कह देना था कि मैंने वह बंद कर दिया। आपने उसके लिए कोई फंडिंग प्रोविजन नहीं किया, आपने उस बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं की है। आप सिर्फ कौशल विकास भत्ते के बहाने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बेरोजगारों के साथ जैसा इस बार हुआ है ऐसा अब तक की किसी सरकार ने नहीं किया है। यहां पर जमीनें बेचने की बात की जाती थी और हमें शंका थी कि आप लोग धारा 118 को किसी तरह से स्क्रेप करने की सोच रहे हैं या उसको डाइल्यूट करने की सोच रहे हैं। हमने इनको इसी सदन के अंदर आगाह भी किया, मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में बाहर बहुत बड़े-बड़े भाषण दिए और यह कहा कि हमारी ऐसी कोई सोच नहीं है लेकिन बजट ने इनके मनसूबे साफ कर दिये हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री डॉ0 परमार ने इसको इनसर्ट करवाया ताकि 'हिमाचलियत' बची रहे लेकिन आज आप हिमाचलियत पर चोट करने जा रहे हैं। आप बताएं कि आप पर कहां से दबाव है? 'हिमाचल ऑन सेल' का नारा पहले भी लगता रहा है। आपने अपने बजट में बातों-ही-बातों में क्या बातें कही हैं; क्या आपने इसको पढ़ा कि अफसरों ने इसमें क्या लिखा है या क्या आपने इसको देखा है? इसमें लिखा है कि सरकारी भूमि पट्टे पर देने के लिए, उसके सदुपयोग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जायेगी यानि कि आप रास्ते तलाश रहे हैं। वन संरक्षण अधिनियम व अनुमतियों के लिए आपने इसमें हिम प्रगति के तहत डील करने की बात कही है। औद्योगिक प्लाट को आपने 30 साल की जगह 90 वर्ष पट्टे पर देने की बात लिख दी है। एक रुपये में पट्टे पर जमीनें देने की बात आपने लिख दी है। आपने जो ये बातें लिखी हैं इनसे आपके इरादे साफ हो रहे हैं। हम भी आपको बता देना चाहते हैं कि आप धारा 118 को हाथ लगायें, आप इसमें संशोधन करें, आप इसका

सरलीकरण करें। (---व्यवधान---) यह दस्तावेजों पर लिखा है। मेरी बात को सुना जाए और

12.3.2018/1525/TCV/AG-1

लेकिन अगर पेज़ संख्या चाहिए तो मैं आपको पेज़ संख्या बता भी देता हूं कि किस-किस पेज़ पर ये लिखा है? आपके इरादे क्या हैं? अंदाज़ आपने बदल दिया है लेकिन आपके इरादे नहीं बदले हैं। हिमाचल प्रदेश को न हम बिकने देंगे और न नीलाम होने देंगे।

अध्यक्ष महोदय, ये शराब की बात करते थे। हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाते थे। ये नशे की बात करते थे कि हम नशे का खात्मा करेंगे, लेकिन अब नशे से इन्कम बढ़ाने की बात आ गई है। ये बताये कि ये बात इनके मन में कहां से आ गई है? क्या ये है आपका महिलाओं के प्रति समपर्ण का भाव। इनकी सरकार दावा कर रही है कि पिछले साल के मुकाबले में 400 करोड़ रुपये ज्यादा की शराब हम बेचेंगे। हम 1600 करोड़ रुपये की शराब बेचेंगे। आप शराब से विकास का मकसद तलाश रहे हैं। आपने हिमाचल के बेरोज़गारों को छल्ला है। हिमाचल की महिलाओं को आप कहते रहे हैं कि हम नशा खत्म करेंगे। आज आप प्रदेश में 1600 करोड़ रुपये की शराब बेचेंगे। मंत्री जी हमने कुछ किया होगा, अब हम इस तरफ (विपक्ष) बैठें हैं, अब परफोर्म करने की आपकी बारी है। आपने नौकरियां देने से हाथ खड़े कर दिए हैं और लोगों को शराब पिलाने की बात कर रहे हों। लॉ-एण्ड-आर्डर की आप बहुत बात करते थे। आपकी सरकार लॉ-एण्ड-आर्डर के मुद्दे पर सत्ता में आई है। आप 'गुड़िया प्रकरण' की बात लगातार करते रहे हैं। आपने अपने बज़ट भाषण में लॉ-एण्ड-आर्डर को सिर्फ 8 पंक्तियां दी हैं। आपने 8 लाईनों में हिमाचल प्रदेश का लॉ-एण्ड-ऑर्डर समेट दिया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 महीनों के अंदर प्रदेश में 13 कत्ल हुए हैं और 50 रेप के केस हो चुके हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका सरकारी आंकड़ा है। 60 मॉलेस्टेशन की घटनाएं हुई हैं और 3 हज़ार मामले दर्ज़ हो गये हैं। कांगड़ा में लड़की के साथ रेप किया गया और उसको मार दिया गया। आपके अधीक्षक, पुलिस का बयान आ

रहा है कि ये शिमला कांड से अलग है। उसको आप किस ढंग से डाइलूट कर रहे हैं। आपको लॉ-एण्ड-ऑर्डर की तरफ ध्यान देना चाहिए,

12.3.2018/1525/TCV/AG-2

हैल्पलाइन बनाने से बात नहीं बनेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि इन हारे-पिटे लोगों पर भी कुछ निकेल डालो। ये जो गुण्डागर्दी करके लोगों पर झूठे केस बना रहे हैं, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। यहां नेशनल हाई-वे की बात की जा रही है। पिछले 2 सालों से 69 नेशनल हाईवेज़ बन रहे हैं और मुख्य मंत्री जी ने भी इनका उल्लेख किया है। आपने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास होगा और उस पर आपने वोटें भी हासिल की हैं। आप हमें यह तो बतायें की राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अब तक कितना पैसा आ चुका है? अब माननीय मुख्य मंत्री जी के पास लोक निर्माण विभाग भी है। ये बतायें कि राष्ट्रीय राजमार्ग कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे? क्या आपकी सरकार में ये बन भी जाएंगे या नहीं? क्या आपने इनकी डी0पी0आर0 बनाने की कोई समय-सीमा निर्धारित की है? अभी तक आप कंसल्टैंट अप्वाईंट नहीं करवा पा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया है कि 31 मार्च तक कंसल्टैंट अप्वाईंट हो जाएंगे। क्या माननीय मुख्य जी इस बात से एश्योर है। अब तो ये लोक निर्माण मंत्री भी है, इसलिए जल्दी से फैसला लें। एच0पी0 स्टेट रोड प्रोजैक्ट श्री वीरभद्र सिंह जी लाये थे और एच0पी0 स्टेट रोड प्रोजैक्ट की हम पूरी तैयारी करके गये हैं। उसकी हमने पूरी तैयारी कर दी थी और वर्ल्ड बैंक को प्रस्तावित भी कर दिया है। आप बताये, आपने इसमें क्या किया?

12-03-2018/1530/NS/DC/1

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, हमारे परिवहन मंत्री जी यहां पर नहीं बैठे हैं और लगातार खबरें आ रही हैं कि अकाली दल के प्रधान सुखवीर बादल व उनका परिवार वोल्वो बसों के बिज़नैस पर कब्ज़ा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस समय लगभग 200-250 वोल्वो बसें चल रही हैं। यह एकाधिकार सही बात नहीं है। सरकार बताये कि monopolization and cartelization of buses जो हो रही है, क्या यह

इनकी सहमति से हो रही है और क्या परिवहन मंत्री जी से उन्होंने पूछा है? ये बसें धर्मशाला, डल्हौज़ी, मनाली और शिमला में लगातार चल रही हैं। इनको चैक करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय, मैंने आपका बयान भी पड़ा है। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि cartelization हो रही है और सारे रूट्स और सारी बसें उन्होंने खरीद ली हैं तथा उनसे एफिडेविट भी ले लिये हैं कि आप आगे से हिमाचल प्रदेश में बसों को कारोबार नहीं करेंगे। अगर यह बड़ी ऊंची शख्सियत है तो मंत्री जी, आपको इसमें दख़ल देने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि एच0आर0टी0सी0 घाटे में चली जाये। एच0आर0टी0सी0 का भी वोल्वो में बहुत बड़ा स्टेक है। मंत्री जी, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इंस्टीच्यूशन्ज़ को बंद करने की बात है। हमने पहले भी कहा है कि आप इंस्टीच्यूशन्ज़ को बंद करने के इरादे को त्याग दो। मुख्य मंत्री जी, जंजैहली आपका अपना विधान सभा क्षेत्र है और हम इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन यह जरूर कहना चाहते हैं कि जन भावनओं के अनुरूप आप जल्दी-से-जल्दी कोई हल निकालें क्योंकि किसी विषय को बहुत ज्यादा लटकाना अच्छी बात नहीं है। आप प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और यह इलाका आपका अपना है। अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी कह रहे थे कि हम 103 इन्स्टीच्यूशन्ज़ की समीक्षा कर रहे हैं और इनमें से कुछ को हम बंद भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी आग है और यह फिर भड़क जायेगी। ऐसा करने की आप कोशिश न करें। उद्योग मंत्री जी ने बयान दिया है कि मैं दलाश का तकनीकी कॉलेज बंद कर रहा हूं। इनका बहुत बड़ा बयान अख़वार में छपा है। ---(व्यवधान)--- जैसे भी खोला है, हमने आपको कह दिया है कि आप इस कॉलेज को चलाने की कोशिश करें।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप समय ले करके अपनी बात कहें।

12-03-2018/1530/NS/DC/2

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को समझायें कि कब बोलना है? दलाश के लोग मुख्य मंत्री जी से मिलने आये थे और मुख्य मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है, वह इनको मालूम होगा।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह जय राम की सरकार है और यह राम राज्य की सरकार है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ठीक ढंग से इसको चलाओ, कहीं राम राज्य की कल्पना करते-करते राम-राम ही न हो जाये। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ---(व्यवधान)--- जो भी यहां कुर्सी पर बैठता है, उसको ऐसा ही लगता है। आप भी पहली बार आये हैं और आपको भी यही लग रहा होगी कि यह कुर्सी मेरी है। अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार को कहा था कि हम विकास में आपका सहयोग देंगे। आपका चयन आया तो हमने कहा कि आप सर्वसम्मति से इस कुर्सी पर विराज़मान होने चाहिए। अभी नड्डा जी के सीट की चयन की बात आई तो हमने कहा कि उनका चयन सर्वसम्मति से हो जानी चाहिए क्योंकि वे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसलिए हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। लेकिन मुख्य मंत्री जी सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं कि मुझे कांग्रेस की कोई परवाह नहीं है। मुझे इन लोगों की कोई परवाह नहीं है। इनके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि

"हर इक बात पे कहते हो कि तू क्या है,

तुम्हीं कहो ये अन्दाज़े गुफ्तगू क्या है?"

जब बार-बार मंचों से आप कहते हैं कि कांग्रेस का सफाया हो गया, वामपंथी का भी सफाया हो गया। आप इतना गरूर मत करो कि आप उस तरफ (सत्ता पक्ष) चले गये हो।

अध्यक्षः मुकेश जी, एक मिनट। मंत्री जी आप कुछ कहिए। ---(व्यवधान)--- चलो इसके बाद बोल देंगे। ठीक है मुकेश जी, आप बोलिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक क्षेत्र निधि के बारे में बोलना चाहता हूं। इसके लिए हम माननीय वीरभद्र सिंह जी के आभारी हैं जिन्होंने यह निधि एक करोड़ दस लाख तक पहुंचायी

12.03.2018/1535/RKS/DC-1

मुख्य मंत्री जी को निधियां बढ़ाने का मौका मिला था परन्तु ऐसी तंगदिली भी क्या हो गई कि आप 15 लाख, 2 लाख रुपये ही बढ़ा रहे हैं। जब हमने विधायक निधि 1.10 करोड़ रुपये तक पहुंचाई थी तो हमें भी पता था कि आपके 23-30 मैम्बर्ज़ हैं। लेकिन आपके मैम्बर्ज़ कह रहे हैं कि यह निधि उन 21 मैम्बर्ज़ (विपक्ष के मैम्बर्ज़) को भी देना पड़ेगी। यह लोकतंत्र है।

यदि आप इस विधायक निधि को 2 करोड़ रुपये करते तो आपको एम.एल.एज. याद करते। अगर आप इस निधि को 10 लाख रुपये करते तो विधायकों के पास पैसा खर्चने के लिए होता और वे आपको याद करते। लेकिन आपने मामूली बढ़ोतरी करके बात खत्म कर दी।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में या तो योजनाएं निरंतरता में हैं या उनके नाम बदले हैं या उनका नामकरण किया है। यहां पर सब पीठ थपथपा रहें हैं कि पता नहीं, क्या बड़ा काम कर दिया?

अध्यक्ष महोदय, 'खाद्य उपदान योजना' पहले से चली आ रही है। इस योजना के लिए 220 करोड़ रुपये का प्रावधान होता है और वह प्रावधान अब भी किया है। 'सस्ता राशन दुनिया को देना है' -वह बड़े लम्बे अरसे से श्री वीरभद्र सिंह जी ने शुरू किया था।

मुख्य मंत्री 'खेत संरक्षण योजना' कांग्रेस सरकार ने चलाई थी और यह वही योजना है। 'डिजिटल राशन कार्ड' पहले से चल रही है। 'पॉली हाउस योजना' और 'एंटी हेल नेट योजना' पुरानी योजना है। बागवानी विकास के लिए जो 1134 करोड़ रुपये का प्रावधान है, उसमें श्री महेन्द्र सिंह जी बहुत शोर मचा रहे हैं। परन्तु यह भी पहले से चला आ रहा है। आप ऐसा दिखावा मत करो कि मैं 1134 करोड़ रुपये ले आया हूं।

'फूड प्रोसैसिंग' यानी आलू का कारखाना पहले प्रदेश में कहीं भी लग सकता था। लेकिन आप कहते हैं कि हम इसे कांगड़ा और कुल्लू में ही लगाएंगे। यह कारखाना पूरे प्रदेश में क्यों नहीं लगेगा? यदि कोई आलू वाला आना चाहता है तो इस कारखाने को पूरे प्रदेश में लगने दो।

12.03.2018/1535/RKS/DC-2

'बेटी है अनमोल योजना' पहले से चल रही है। 'मदर टैरसा आश्रय सम्बल योजना' पुरानी है। श्री वीरभद्र सिंह जी ने 'गौवंश विकास बोर्ड' चलाया और आपने इसे 'गौ सेवा आयोग' कर दिया। 'मुख्य मंत्री वर्दी योजना' को आपने 'अटल वर्दी योजना' कर दिया। 'कौशल विकास योजना' को आपने 'दीन दयाल उपाध्याय योजना' कर दिया। 'आदर्श जीवन वृत्ति

परामर्श केंद्र' को आपने आदर्श कैरियर परामर्श कर दिया। 'हिमालयन पर्यटन सर्किट' को आपने 'धार्मिक सर्किट' कर दिया।

बिजली के क्षेत्र में, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के उपदान में आज कोई पहल नहीं हुई है। आपने कहा कि हम 475 करोड़ रुपये दे रहे हैं। यह सब्सिडी हमेशा से दी जाती है, लेकिन आप इसको किस ढंग से रिप्रेजैंट कर रहे हैं? जैसे बहुत बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। सी.एम. राहत कोष से लोगों की मदद की जाती है। आपने 'मुख्य मंत्री चिकित्सा योजना' शुरू कर दी ताकि सरकारी कोष से 10 करोड़ रुपये लिए जा सके। मुख्य मंत्री राहत कोष में दुनिया फंड्स देती हैं, उसके तहत मुख्य मंत्री लोगों के इलाज़ व शादियों में मदद करते हैं। आप सरकारी कोष से 10 करोड़ रुपये घूमा रहे हैं।

मुख्य मंत्रीः क्या इस योजना पर भी आपको ऐतराज़ है?

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः सर, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप जो मर्जी करो। ..(व्यवधान)... आप योजनाओं का नाम किस ढंग से बदल रहे हैं? ..(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, जैसे मुख्य मंत्री जी इतरा रहे थे कि मैंने 28 योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं कैसे शुरू की गई इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। 'अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती'। यह क्या योजना है? जो लोग उस स्कूल से निकले हैं उनको हम ऐनुअल डे पर प्राइज़ देते हैं, उनको बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि एक स्पेशल डे फिक्स किया जाएगा। आप किसको मूर्ख बना रहे हैं कि मेरे स्कूल से निकले मोती। उनको हम सम्मानित करते ही हैं। जो सिविल सेवाएं या दूसरी कोई प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें लोगों को पैसा दिया जाता है। आप कहते हैं कि 'मेधा प्रोत्साहन योजना' नई योजना आ

12.03.2018/1535/RKS/DC-3

गई। आपको यह सुझाव किसने दिया कि आप बीच में इस ढंग की योजनाएं इन्सर्ट करो। हैरिटेज गाइड जगह-जगह पर हैं और आपसे नाम लिखवा दिया 'आज पुरानी राहों से'। आपने इसका नाम इस तरह से कर दिया। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति

जागरूक करने के लिए बहुत से मंच हैं। उनके माध्यम से ज्यादा ज्ञान भी दिया जा रहा है। आपने कह दिया- 'सशक्त महिला योजना'। आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? आपने इन योजनाओं को किस ढंग से पेश किया है। मुख्य मंत्री जी यह आपने नहीं किया, आपसे यह खिलवाड़ अफसरशाही ने करवाया है। जो योजनाएं निरंतरता में चल रही थी उनका नाम आपने बदल दिया।

12.03.2018/1540/बी0एस0/एच0के0-1

श्री अग्निहोत्री द्वारा जारी....

इस ढंग से आपने यह सारा कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, कह रहे हैं कि बिजली में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। जब हमने बजट पढ़ करके देखा तो इसमें लिखा है कि 182 मैगावाट पूरे साल बिजली पैदा करेंगे।

पर्यटन को बढ़ावा देने की इन्होंने बात कर दी "नई मंजिले नई राहें " की बात कर दी। कहा कि पूरे प्रदेश में पर्यटन बहुत चलेगा। अध्यक्ष महोदय, बजट में 50 करोड़ दिया है। मुख्य मंत्री जी ने यहां पर लम्बा-चौड़ा भाषण दिया और कहा कि मेरी प्राथमिकता पर्यटन है और पर्यटन में आप 50 करोड़ रुपया दे रहे हो।

लैपटॉप का आपने कोई जिक्र नहीं किया है। आदर्श विद्यालय माननीय वीरभद्र सिंह जी के समय जगह- जगह बन रहे थे। अब आपने उसका नाम बदल कर कह दिया कि आदर्श विद्या केन्द्र होंगे। किस ढंग से आप इन चीजों को पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इधर मुख्य मंत्री जी ने कहा "सतत् विकास लक्ष्य" इसके तहत इन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो निर्धारित मानक हैं वे 2030 में पूरे होने थे। वह हम 2022 में पूरे कर लेंगे। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, दो महीनों में 8 साल का फर्क आ गया? दो महीनों में इन्होंने 2030 का टारगेट 2020-22 तक पहुंचा दिया। इन्होंने कहा 13 फॉरन फंडिंड प्रोजैक्ट 15320 करोड़ से बनेंगे। क्या दो महीने में ये सारी बतें हो गई? क्या यह आपकी बदौलत है? अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से यह बजट पेश किया गया है, हम तो चाहते थे कि माननीय

मुख्य मंत्री पहली साल में कोई रोड़ मैप तैयार करते, बताते कि किधर हिमाचल जो जाना है। कहां से रिसोर्स जनरेशन होने हैं। कहां से फंडिंग होनी है। लेकिन मुख्य मंत्री जी तो छोटी- छोटी रियायतों में फंस कर रह गए। हमारे शिक्षा मंत्री जी ट्रांस्फर नीति बना रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है एक लाख के आस-पास शिक्षक हैं, देखना कहीं ऐसे ही बिना अध्यापकों से कंसल्टेशन किए कोई नीति एनाऊंस कर देना। यह बहुत खतरनाक महकमा है। इसलिए पहले बात कर लें। शिक्षकों की भी 200-250 युनियनें हैं। उन सब को पहले विश्वास में ले लेना तभी ऐसा कोई निर्णय लें।

12.03.2018/1540/बी0एस0/एच0के0-2

अध्यक्ष महोदय, सरकार की नजरे मंदिरों के चढ़ावे तक पहुंच गई। मंदिरों को कुछ देने की बजाय ये मंदिरों के चढ़ावे को ही लेने लग गए, कि किस तरह से मंदिरों का पैसा बाहर निकालना है। मंदिरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते।

मुख्य मंत्रीः पुण्य का कार्य कर रहे हैं।

श्री अग्निहोत्रीः पुण्य का कार्य तो आप कर ही रहे हैं। मंदिरों की सड़के बनवा देते, मंदिरों की ट्यूबलाइट्स लगवा देते। मंदिरों में रहने का बन्दोबस्त कर देते, वह कुछ नहीं किया। यह पहली सरकार है जिसकी नजरें मंदिरों के चढ़ावे तक पहुंच गई। हमारे बहुत दूरदर्शी मुख्य मंत्री हैं।

शिक्षा मंत्रीः आपने तो मंदिरों के पैसे से कैमरे लगा दिए थे।

श्री अग्निहोत्रीः मंदिरों में लोगों को दर्शन के लिए कैमरे लगवाए हैं। आप जरा ध्यान से देखें। मंदिरों के पास कैमरे लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें सब मालूम है, किस तरह से ये चल रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो अपने बजट में दिया है वह छोटी-छोटी रियायतें और प्रोत्साहन राशियां दे दीं। हिमाचल प्रदेश की जनता को छोटे-छोटे लॉलीपॉप दे दिए और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इसका सारा दल और पूरा प्रदेश में इनका तंत्र इनकी पीठ थपथपा रहा है। कहीं-न- कहीं लोक सभा चुनावों का खोफ़ इनको नजर आ रहा है। मंत्री जी लग जाएगा पता । "खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही

जाती है" आपमें आनी शुरू हो गई। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है ये हनीमून पीरियड आपका है, अब खत्म हो जाना चाहिए। इस पीरियड को हनिमून पीरियड को आप समाप्त कर दीजिए और कंफ्यूज़न से सरकार को बाहर ले आओ। बाहर क्या हो रहा है यह देखो। मुख्य मंत्री जी आपके दफ्तर के इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। आपके दफ्तर में जो संघ और आर0एस0एस0 का घेरा है इसको थोड़ा तोड़ो, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। लोग भी कह रहे हैं और अधिकारी भी कह रहे हैं कि घर में ही संघ बिठा दिया, कोई बिना इजाजत के किसी को मिलने नहीं देते। हजारों फाईलें कैसे लटक गई? हमने टायर्ड और रिडायर्ड रखे थे परंतु आई0ए0एस0 थे, आपने जो रखे उनका क्या तजुर्बा है। आप रिटायर्ड-टायर्ड बोलते रहे । (वन मंत्री आपने स्थान पर खड़े हुए) अध्यक्ष महोदय,

12.3.2018/1545/DT/HK-1

आप वन मंत्री जी को बिठाइए नहीं तो यह समय काऊंट नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कुछ छालों का जिक्र किया, पता नहीं इस चुनाव के दौरान किस-किस के पड़े होंगे। लेकिन मैं इन्हें कहूंगाः

यहां लोगो का जीना मौहाल है, पड़े सुविधाओं के लाले हैं,
और वो कहते हैं देखे नहीं किसी ने मेरे पांव के छाले हैं॥

छालों की बात पता नहीं पिछले चुनाव में किस-किस के पड़े होंगे। मैं उस तरफ नहीं जाता। मैं यह जरूर शुभ कामनाएं देता हूं कि आप प्रदेश को आगे बढ़ाओ। इस बजट में जो कमियां रह गई हैं, जो दिशा आपको प्रदेश के लिए देनी थी, जो आर्थिक रोड़ मैप आपको तैयार करना था, उससे आप चूक गए हैं। ऐसी छोटी-छोटी रियायतें कोई भी कर लेगा। लेकिन जो आपको करने का है उस ओर आपको ध्यान देना चाहिए था, जो आपने नहीं दिया । इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस कारण की इस बजट का समर्थन किया जाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि इनके सदस्य बोलेंगे कि यह ठीक है कि पंचायती राज का पैसा बढ़ा दिया, नगर निगम का पैसा बढ़ा दिया। इन छोटी-छोटी रियायतों की बजाय इस प्रदेश का जो पूरा आर्थिक रोड मैप बनना चाहिए था और लम्बी अवधि योजना बननी चाहिए थी, वह

आपने नहीं बनाई। वह आपसे चूक हुई है। आपसे चूक क्या हुई होगी, आपको तो समय नहीं लगा होगा। इसके लिए वही डायरेक्टर और प्रड्यूसर जिम्मवार हैं जो हमारे टाईम भी थे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अतं मे मैं कहना चाहूंगा कि निंदक नियरे राखिए.. हम तो इन्हें आगाह कर रहे हैं। बाकी बुरा मानना या नहीं मनाना यह इनकी अपनी बात है। धन्यवाद।

12.3.2018/1545/DT/HK-2

अध्यक्षः इससे पहले की अगले सदस्य बोलें मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि 7 सदस्यों के नाम आज मेरे पास आ चुके हैं और अभी माननीय उद्योग मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

उद्योग मंत्रीः आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने संस्थान बंद करने की बात यहां पर कही है। इनके ध्यान में मैं एक बात लाना चाहता हूं कि दलाश तकनीकी कॉलेज की नोटिफिकेशन 08 अक्तूबर, 2017 को हुई है और 14 अक्तूबर, 2017 को अचार सहिंता लगी है। इस प्रकार के संस्थान आपने केवल कागजों के ऊपर खोले हैं, जिनका जमीन के ऊपर कुछ नहीं है। मैं तो चाहूंगा आप मेरे साथ चले और वहां जा करके देखें। आप मेरी पूरी बात सुनिए । आपने जो कुछ लास्ट के दो महीनों के अन्दर किया है उसमे से एक नमुना यह भी है। आपने कागज़ो के ऊपर संस्थान खोले हैं। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह सरकार आदरणीय जय राम ठाकुर जी की है, जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने खोलने की बात की है। हम वहां पर इसे खोलेंगे। परंतु सबसे पहले वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, पोस्टें क्रिएट करेंगे उसके बाद इसको खोलेंगे। हम बंद करने की बात नहीं कह रहे है। लेकिन आपने जो कागजों के ऊपर किया है। इस प्रकार की नोटीफिकेशन जो आपने 08 अक्तूबर, 2017 को की है, ऐसी एक नहीं सैंकड़ो में हैं। लेकिन हमारी सरकार जमीन के ऊपर संस्थान खोलेगी। हम आपकी तरह नहीं करेंगे कि आपने आते ही जितने संस्थान पिछली सरकार ने खोले थे, आपने आते ही बंद कर दिए। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट तक

भुगता है। इसलिए यहां पर जो काम होगा वह धरातल के ऊपर होगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पोस्टें क्रिएट होगी, अध्यापक लगेंगे और गुणवत्ता के आधार पर सारे काम होंगे।

12.3.2018/1545/DT/HK-3

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुकेश अग्निहोत्री जी ने एक बात कही है कि यहां जो स्थानीय लोगों की वोल्वो बसें हैं, वह बाहर की कम्पनियों के द्वारा खरीदी जा रही है। यह विषय अत्यंत चिंता जनक है। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इन सब के पीछे यदि कोई करण रहा है तो कहीं-न-कहीं जब आप सत्ता में रहे वहीं कारण रहा है। अभी जितनी वोल्वो बसें हिमाचल प्रदेश की चाहे कुल्लू , मण्डी , धर्मशाला की है,

12.03.2018/1550/SLS-YK-1

माननीय वन मंत्री ... जारी

अभी जितनी बसें बिकी हैं इन लगभग सभी बसों में से हिमाचल प्रदेश में कोई बस रजिस्टर्ड नहीं है। उनका कोई दिल्ली का नंबर है, कोई पंजाब का तो कोई हरियाणा का है। कारण यह है कि पिछले 5 साल की सरकार में आपने हिमाचल प्रदेश के ऐंटरप्रेन्योर को यहां गाड़ियां नहीं खरीदने दीं; उनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में मण्डी की 2 गाड़ियों को आपकी पूर्व कांग्रेस सरकार के समय अनुमति दी गई थी और वह भी माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि इनको 15 दिनों में अनुमति दो। कारण यह रहा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली नंबर की गाड़ियों को बाहर की कंपनियों ने डरा-धमकाकर खरीदना प्रारंभ किया। आपके 5 साल के कार्यकाल में आपके उस समय के परिवहन मंत्री सड़क पर आते थे और हिमाचल के ऐंटरप्रेन्योर की बसिज को डरा-धमकाकर बंद करते थे, उनका चालान करते थे जबकि बाहर की बसों को खुलेआम चलने देते थे। अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए कि बाहर की बसों के कितने चालान हुए तो पता

चल जाएगा। मंत्री स्वयं सड़क पर खड़ा होकर यह करता था। हिमाचल के ऐंटरप्रेन्योर को इस तरह पिछले 5 सालों में घाटे में पहुंचाया गया। यह प्रोसैस लंबे समय तक चला। लेकिन, मैंने पहले भी कहा है और यहां भी कह रहा हूं कि अगर इस ढंग का कोई माफिया होगा; हमने ऐफेडैविट में लिखा है कि इस तरह के कारवां दोबारा नहीं आएंगे और यह सब-के-सब डाक्युमैंट्स हम इकट्ठे कर रहे हैं। अगर ऐसी मोनोपली है तो अब यह ठाकुर जय राम जी की सरकार है, हम हिमाचल प्रदेश में ऐसी मोनोपली को सहन नहीं करेंगे और न हम ऐसे माफ़िया की मोनोपली चलने देंगे।

दूसरी बात आपने मंदिरों के बारे में कही है। मंदिरों का विषय मेरा नहीं है लेकिन कुल्लू का वैष्णों माता का मंदिर वहां सबसे बड़ा मंदिर स्थान है। यह ठीक है कि बहुत से धार्मिक स्थान ऐसे हैं जो वन विभाग की भूमि पर बने थे, लेकिन आपकी सरकार के समय में उस समय के वन मंत्री और आपकी सरकार ने, जहां पर इतने अधिक सेवाकार्य होते हैं, फ्री का लंगर चलता है, एक्युप्रैशर, एक्युपंक्चर से इलाज

12.03.2018/1550/SLS-YK-2

होता था, बच्चों की बहुत अच्छी लाईब्रेरी थी, धार्मिक कीर्त्तन आदि होता था, आपके लोगों ने वहां जाकर जबरदस्ती उस मंदिर को तोड़ा। उसकी बिजली भी काटी, पानी भी काटा और बाद में कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय है जबकि माननीय उच्च न्यायालय को कोई भी इस तरह का आदेश नहीं था। उसको जनरालाईज किया गया। वहां पर जो साध्वी माता है वह अब तक बिना बिजली-पानी के रही। आपने मंदिर के नाम पर भी यह सब किया।

माननीय सदस्य ने एक बात और कही। मैं बार-बार आपकी स्टेटमैंट्स पड़ता रहता हूं। आपने कहा कि 'मुख्य मंत्री कार्यालय में कौन आए, कौन जाए।' मैं यह नहीं कहता कि वहां पर सब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग हैं। वह भी होंगे, बाकी भी होंगे; सबके लिए दरवाजा खुला है। लेकिन इस विषय को बार-बार कहना ठीक नहीं है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक बात कही जाती है कि सन् 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय पठानकोट, पंजाब में सारा ट्रैफिक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने

संभाला था। जब 26 जनवरी को दिल्ली में परेड़ हुई तो उस समय के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों को उस परेड़ में शामिल होने के लिए बुलाया और उस परेड़ में संघ के लोग सम्मिलित हुए। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री कार्यालय में भी सबके लिए दरवाजा खुला है। संघ के लोग हों या किसी भी विचारधारा से हों; चाहे कांग्रेस विचारधारा के हों या कम्युनिस्ट आइडियोलोजी के हों, भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के लोग हमारे यहां रहते हैं। वहां सबके लिए दरवाजा खुला है। लेकिन कंडिशनल किसी के लिए नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि बार-बार यह कहना उचित नहीं है। वहां कंडिशनल कोई नहीं है, सबके लिए दरवाजा खुला है, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए खुला है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले यही लोग टायर्ड-रिटायर्ड की बात करते थे। उस समय इनका यही विरोध था कि वहां पर रैगुलर लोग बैठने चाहिए। अब टायर्ड-रिटायर्ड की जगह आपने कौन बिठा दिए, हम तो आपसे केवल यही पूछ रहे हैं।

12.03.2018/1550/SLS-YK-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस छोटे से ही कार्यकाल में हमारे मित्रों को इतनी परेशानी हो जाएगी, यह मुझे मालूम नहीं था। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे ऐसे वक्त बीच में आए जब बोलने का मन किया था लेकिन मैं बोला नहीं। इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो काम मैं पहली बार यहां से कर रहा हूं, भाई साहब भी पहली ही बार वह काम वहां से कर रहे हैं।

12/03/2018/1555/RG/YK/1

मुख्य मंत्री-----जारी

इसलिए कम-से-कम मुझे लगा कि इतना लिहाज़ तो मुझे रखना चाहिए। इसलिए हमने प्रयत्न किया और नहीं बोले।

अध्यक्ष महोदय, मेरे कार्यालय में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। यह विषय इनके इतने महत्व का बन गया। मुझे सचमुच में इसकी ऐसी कल्पना नहीं थी। मेरे कार्यालय में कौन चाहिए, कम-से-कम इस काम को तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री वीरभद्र सिंह जी के कार्यालय में कौन होना चाहिए था, वह इनके महत्व का था। ---(व्यवधान)----

मुख्य मंत्री : सुनिए, हम एक बात कह रहे थे। वहां सचिवालय के एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे अधिकारी थे जो सेवा निवृत्त थे। लेकिन मेरे कार्यालय में तो कोई भी सेवा निवृत्त नहीं है। ओ.एस.डी. एक अलग व्यवस्था होती है। लेकिन मेरे कार्यालय में मुझे बताइए, मेरे प्रमुख निजी सचिव से लेकर Principal Private Secretary to Chief Minister और सबके सब जितने भी अधिकारी हैं वे सब वर्तमान में सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर भी बहुत आश्चर्य हुआ कि दो महीने के बाद ही इतना परिवर्तन आ गया कि जो अधिकारी अपना पक्ष इस माननीय सदन में नहीं रख सकते, ये खुलेआम उन पर टिप्पणी करने चल पड़े। उन्होंने अपना काम करना है। बजट के लिए विज़न किसने देना है? यह नेतृत्व तय करता है। जो हमने तय किया। अधिकारी उसमें सहयोग करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था के प्रति कम-से-कम हमारी इतनी जिम्मेवारी तो होनी चाहिए कि हम उस व्यवस्था का सम्मान करें।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं --(व्यवधान)----

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी को पहले अपना भाषण तो समाप्त करने दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब ये बोल रहे थे, तो मैं नहीं बोला।

12/03/2018/1555/RG/YK/2

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने 9 मार्च को अपना भाषण दिया, हमने उसको बिल्कुल प्यार से सुना और इनकी ख़बरें अखबारों में अच्छी छपीं। ---(व्यवधान)---

मुख्य मंत्री : इसलिए आपका भाषण भी हमने प्यार से सुना और हम बीच में नहीं बोले। तो आपको ख़बरें छपने पर आपत्ति है। हमारी अच्छी खबर छपती है, तो भी आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन बिन्दुओं पर बोलूंगा। मुझे पीड़ा तो इस बात की हो रही है कि आपने वास्तविक स्थिति को लेकर और आंकड़ें लेकर भी गलत बोल दिया। जो आपके समय में हुआ, उसको हमारे खाते में डाल दिया और हमारे समय का काम अपने खाते में डाल दिया। यह गलत है क्योंकि मैं आंकड़ो में जाना नहीं चाहता। जब मैं इस सारी चर्चा का उत्तर दूंगा, उस दिन सारी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करुंगा। मंदिरों के पैसों की अगर बात कर रहे हैं, तो मंदिर तक हाथ पहुंच गया। अध्यक्ष महोदय, हम तो बहुत ही पावन कार्य में मंदिर के धन का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन यहां क्या उपयोग होता रहा?

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, ये कहीं-न-कहीं हिन्दू एजेण्डे को प्रभावी कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री : यह होना चाहिए। यह हमारा धर्म है और मुझे इस बात पर गर्व है। अगर गाय को मॉ की संज्ञा दी है और मॉ के प्रति हमारा श्रद्धा एवं आदर का भाव है तो वह हमारा दायित्व बनता है। जिसको हम करेंगे। लेकिन इनके जमाने में मंदिरों के पैसों से बड़ी आलीशान गाड़ियां आती रहीं, मंदिरों के पैसों से आलीशान दफ्तर बनते रहे, मंदिरों के पैसों से किस-किस की सुविधा के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई और मंदिर ट्रस्ट से क्या-क्या किया गया? ये सारी चीजें हैं। अगर हम ये कहने लगेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं। हमने पावन और पवित्र भावना से इस दिशा में एक बात कही है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : मंदिर के पैसे से मंदिर का जीर्णोद्वार ---(व्यवधान)---

मुख्य मंत्री : आपने क्या किया, वह भी हम कह रहे हैं। ---(व्यवधान)---

12/03/2018/1555/RG/YK/3

अध्यक्ष : अग्निहोत्री जी, कृपया मुख्य मंत्री जी को बोलने दें। आप बैठ जाएं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ऐसे बार-बार खड़े होने की आदत किसी को रही होगी, तो इनको ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : यह आदत तो आपको है। आप विपक्ष की बात सुनने को राजी नहीं हैं। ---(व्यवधान)---

मुख्य मंत्री : मैं तब बोल रहा हूं जब आप बैठकर बोल रहे हैं। हम खुले मन से कहते हैं। --(व्यवस्था)---

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, ---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : माननीय मुकेश जी, कृपया बैठ जाएं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सचमुच में इनके सामने अपने आपको इस तरह से स्थापित करने की बहुत बड़ी चुनौती है। सामने बैठे नेता के सामने ये अपनी परफॉरमैंस देना चाह रहे हैं, यह परफॉरमैंस का मसला है और अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ---(व्यवधान)---

12/03/2018/1600/MS/AG/1

मुख्य मंत्री जारी-----

अच्छा होता अगर ये सुझाव देते तो हम उन सुझावों का अभिनन्दन करते। -(व्यवधान)- क्योंकि अध्यक्ष महोदय, वहां (पक्ष की ओर इशारा करते हुए)की परिस्थिति ऐसी है कि बहुत से लोगों से बाइपास होकर ये आगे पहुंचे हैं। ऐसी परिस्थिति है और इस बात को मैं समझता हूं। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। -(व्यवधान)- मैं तो एक स्थापित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर बैठा था। यह ईश्वरीय कृपा है जिसकी वजह से मैं यहां हूं। मैं यहां आपकी मेहरबानी से नहीं हूं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अगर आप पर ईश्वरीय कृपा है तो हो सकता है कि हम पर भी वही कृपा रही होगी।

12/03/2018/1600/MS/AG/2

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री राकेश पठानिया जी भाग लेंगे।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, जो आदरणीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने 9 मार्च को इस मान्य सदन में बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मुकेश अग्निहोत्री जी ने अपने भाषण में जिस तरह से सभी तथ्यों को तोड़-मरोड़कर यहां पेश करने का प्रयास किया, वह सुनकर मुझे बड़ा आनन्द आया । -(व्यवधान)- बिल्कुल मैं जोड़ने का ही काम करूंगा। जिनके अपने घर शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अब मैं अपने भाषण को कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी दो महीने पहले बनी सरकार के पहले बजट के बाद इनमें इतनी बौखलाहट है तो साल के बाद क्या होगा, इस बात को तो भगवान ही जानें? आप लोगों ने पिछले पांच सालों में क्या कुछ नहीं किया, पहले इस पर चर्चा करें या किस पर चर्चा करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस तरीके से आपने इस प्रदेश को नुकसान करके छोड़ा है उसका ही नतीजा है कि आप विपक्ष में बैठे हैं और ये पक्ष में बैठे हैं। फिर आप छोटी-छोटी बातों पर जो हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हैं कहते हैं कि आप वहां कैसे आ गए। अब आपके पेट में क्यों मरोड़ पड़ रहा है? अब कौन कैसे आ गया तो संघ का कार्यालय है और संघ का आदमी अगर कार्यालय में आ गया तो क्या आपकी परमिशन लेकर वह वहां आएगा? आज यहां सामने जो ये सारी-की-सारी टीम बैठी है ये संघ की ही एक प्रोडक्शन है और तभी ये लोग यहां बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा हैरान हूं जैसे इन्होंने कहा कि रिसोर्सिज के ऊपर कोई बात नहीं की गई। पांच साल आपकी सरकार रही और आपने रिसोर्स डवलपमैंट कमेटी या सब कमेटी बनाई। पांच साल में आपकी इस कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई और आपके मुंह

से यह रिसोर्स डवलपमैंट बड़ा अच्छा शब्द लग रहा है? अन्य भी आपने जो-जो बातें कहीं, जैसे आपने कहा कि हम आपकी धारा 118 के

12/03/2018/1600/MS/AG/3

बारे में कुछ नहीं सुनना चाहेंगे। A glaring illegality has been committed by the previous Government. ये कोरिन होटल नाम की क्या चीज है और ये रेणु कोरिन जो सोलन के बड़ोग की थी, कौन थी जिसको आपने अरबों रुपये की जमीन कैबिनेट में से पास करके दे दी? It is still illegal. The Supreme Court has let it down. मैं यहां 50 उदाहरण दे दूंगा जहां पर धारा 118 की उल्लंघना आपकी सरकार ने की। There is not one reason or not one occasion कि जहां पर आपने सरकार का दुरूपयोग नहीं किया।

इसी तरह से आपने बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण युवाओं के ऊपर दे दिया कि युवाओं को हमने मिसलीड किया इसलिए सारे युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ चल पड़े। वास्तविकता यह है कि आपका अनएम्प्लॉयमैंट अलाऊंस का झूठ युवाओं से बर्दाश्त नहीं हुआ। साढ़े चार साल के बाद आपके ही मंत्री रोने लग पड़े कि ये क्या है। आपने बेरोजगारी भत्ते की जो बात कर रखी थी, वह एनाऊंसमैंट कहां है? आपके मंत्रियों ने पब्लिक में जाकर बवाल खड़ा किया और आपके मंत्रियों ने ही जाकर हमारे युवाओं को बताया कि आपने एक अनाऊंसमैंट की हुई थी कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। पद यात्रा आपका मंत्री निकाल रहा है और अनएम्प्लॉयमैंट का ठीकरा आप हम पर फोड़ रहे हैं? केवल 22000 बच्चों को आपने जाते-जाते बेरोजगारी भत्ता देकर एक टोफी उनके मुंह में डाल दी।

12.03.2018/1605/जेके/एजी/1

यहां पर आँगनवाड़ी से लेकर आशा वर्कर तक और प्रधान, जिला परिषद् का मानदेय बढ़ रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है । आप बोल रहे हैं कि उनको टॉफी दे दी। मुझे कोई कम्पेरिजन स्टेटमैंट नजर नहीं आ रहा , आप जो बात करना चाह रहे हैं लेकिन आपकी (****) ठीक नहीं है। इस बात का डर है क्योंकि 28 नई स्कीमें...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, राकेश पठानिया जी द्वारा जो (***) की बात की है उसको कृपा डिलीट करें।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बोल रहा हूं, संगठन के बारे में बोल रहा हूं। मुकेश जी, मैं आपकी बात पूरे ध्यान से सुन रहा था। आपने इतनी ज्यादा बातें बोली और अपने 45 मिनट के भाषण में आपने यह समझाने का प्रयास किया कि अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं और न ही कुछ करने की हमारी इच्छा है और जो कुछ किया है वह आपकी सरकार ने ही किया है। 80 से 70 साल तक बुढ़ापा पैंशन मिलनी शुरू हो गई। उसमें श्री जय राम जी ने क्या गलत कर दिया? 68 नेशनल हाई वेज़ आपके पास आ गए उसमें आपके दो साल में कुछ नहीं हुआ। आपसे डी0पी0आर्ज0 तक नहीं बनी। स्वास्थ्य संस्थानों का किस तरह से दुर्दशा हुआ? भारत सरकार की तरफ से आपको क्या-क्या लाभ नहीं मिले। एम्ज जैसा अस्पताल यहां पर आ गया क्या एक बार भी आपने स्वागत करने का प्रयास किया? Financial mess आपने यहां पर क्रियेट कर दी। हमारी सरकार ने, हमारे संगठन ने लगातार पिछले दो वर्ष से संघर्ष किया। हमने बार-बार कहा कि माफिया राज़ इस प्रदेश को लूट रहा है। आज प्रश्न भी लगा था। मेरा विपक्ष के नेता से भी निवेदन रहेगा कि आप भी हमारे साथ आएं। मैं आपको वहां पर दिखाऊं कि खड्डों का क्या हाल है और चक्की खड्ड का क्या हाल है? आपका विभाग था और आप मंत्री थे। The way that lands have been raped by that mafia. अध्यक्ष महोदय modus operandi क्या है। अब मैं

(***)**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

12.03.2018/1605/जेके/एजी/2

माफिया में आ रहा हूं कि जहां पर आपकी माइनिंग लीज़ है उस माइनिंग लीज से 25-50 किलोमीटर दूर जा कर भी माइनिंग हो रही है। लोगों को ड्रग्ज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है। बच्ची की शादी के लिए एक लाख रूपया दिया जा रहा है। बेटे को मोटर साइकिल ले कर दिया जा रहा है फिर उस जमीन को लीज़ पर लिया जा रहा है यह कह कर कि हम जमीन केवल 2 साल के लिए लीज़ पर ले रहे हैं। फिर वहां पर पोकलैंड्ज़ को लगा करके, मैंने

चक्की खड्ड के ऊपर खड़े हो करके दृश्य देखे हैं, एक-एक हजार मशीन वहां पर है और ऐसा लगता है कि चण्डीगढ़ का सेक्टर बन रहा है। एक-एक हजार मशीन वहां पर कई सैंकड़ों किलोमीटर तक खनन कर रही है। वह हजारों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि आज वहां पर खंडहर बन कर रही गई है। आप विभाग के मंत्री थे । क्या किया खनन माफिया का? नूरपुर से शुरू हो कर नालागढ़ तक आ जाओ। आपके विधायकों के क्रशर थे। (व्यवधान) जो विधान सभा में थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी आपको मुख्य मंत्री जी बता कर हटे कि जो लोग इस समय उपस्थित नहीं है, इन्डायरैक्टली आप जिस ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करने का प्रयास कर रहे हैं, यह बात उसी एंगल पर आ रही है। मुकेश जी, मैं आपसे केवल एक विषय पर बात कर रहा हूं कि आपने शिक्षा के ऐसे-ऐसे संस्थान खोल दिए, आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी की मैं बहुत इज्ज़त करता हूं लेकिन जितनी बार जिस विधायक के विधान सभा क्षेत्र में टूअर होता था, घोषणा हो जाती थी। कहीं 11 मिडल स्कूल थे तो वे 11 सीनियर सैकंडरी हो गए। मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हू। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 180 बोर्ड लगे हैं लास्ट तीन महीनों में कि इसके लिए इतनी धनराशि, उसके लिए इतनी धनराशि लेकिन एक फुटी कौड़ी की व्यवस्था नहीं है। You have created a financial mess with the State. आज आपको जय राम जी की तरफ ऊंगली उठाने का कोई हक नहीं बनता क्योंकि ये सारा का सारा जो मिसमैनेजमैंट है, यह आपकी ही देन है। फिश पौंड के माध्यम से क्रशिंग होती है। मैंने आर.टी.आई. डाली कि कितनी मच्छी पैदा होती है ।

12.03.2018/1610/SS-DC/1

श्री राकेश पठानिया क्रमागतः

जवाब यह मिला कि मछलियां नहीं मगरमच्छ पैदा हो गए। ऐसे-ऐसे मगरमच्छ पैदा हो हुए कि हमारी हज़ारों हैक्टेयर जमीन जो कभी जमीन नहीं बन पाई। । am very pained at this. मैं हाथ जोड़कर अपनी सरकार और मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके हमारे लोगों पर थोड़ा रहम करो। इस सरकार (कांग्रेस) ने इतनी बेरहमी से हमारी माइनिंग की है, इतनी बेरहमी से ड्रग माफिया का पालन हुआ, इतनी बेरहमी से वन माफिया का पालन हुआ, आज गोविन्द सिंह ठाकुर ने दो महीने में कॉरेक्टिव मेयर लेने शुरू कर दिए तो आपको तकलीफ है। आज पूरा का पूरा होशियार कांड आपके टाइम में हुआ। गुडिया कांड आपके टाइम में हुआ। आज आप लिखा रहे हैं कि कोटला में क्या हुआ। मुकेश जी, थोड़ा पता तो कर लेना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो कोटला में कांड हुआ, उसमें उस

लड़की और लड़के का एक बहुत लम्बा अफेयर था। जो मोबाईल डिटेल्ज़ मिली हैं उसमें लगातार छः घंटे में कम-से-कम 300 बार दोनों की आपस में बात हुई है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अगर किसी का लव अफेयर हो गया तो क्या उसको मारने की इजाज़त हो गई?

श्री राकेश पठानियाः आप बात तो सुन लीजिए। जो आप रेप एंड मर्डर बोल रहे हैं, यह रेप एंड मर्डर उसी लड़के के माध्यम से हुआ था और वह पकड़ा गया है। सरकार ने तुरन्त ऐक्शन लिया है और 24 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार हुआ है और आज वह जेल के अंदर है। यहां उल्टा हुआ है। यहां अपराधी अंदर हुआ है और आपके टाइम में पूरी पुलिस ही अंदर है। आपने बड़ी अच्छी बात बोल दी कि मुख्य मंत्री जी वहां जाते हैं और बड़े अच्छे-अच्छे बुक्के लेकर फोटो खिंचाते हैं। आपके मुख्य मंत्री जी जब वकीलों के साथ नज़र आते हैं तो हम क्या बोलें? --(व्यवधान)-- मैं मुकेश जी की बात का जवाब दे रहा हूं। आज लगभग 40 परसैंट हाइक पी0डब्ल्यू0डी0 के बजट में मैटलिंग एंड टारिंग के लिए कर दी। आज पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का क्या हाल है, आज पूरे प्रदेश के अंदर इस डिपार्टमैंट की क्या व्यवस्था कर रखी है और मैं फिर इस बात को कॉरैक्ट करना चाहूंगा और कमैंट भी करना चाहूंगा कि two months is too early. परन्तु जो बजट की दिशा है, मार्किट में एक जनरल स्पैकुलेशन पैदा करने का आपने प्रयास किया that this Government has failed. यह सरकार तो अन-एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में है, यह आपने खूब चर्चा की।

12.03.2018/1610/SS-DC/2

But this document of Budget has given a vision in every field that here is a vision and here is a young, dynamic Chief Minister named Shri Jai Ram Thakur, who has a vision to give new direction to this State. मैं छोटी-छोटी बातों पर आ रहा हूं। पहली बार 10 करोड़ का प्रावधान है। मैडम, आपके क्षेत्र में भी लड़के मधु-मक्खी पालन का काम करते हैं। पहली बार सरकार 10 करोड़ रुपया एक छोटे से व्यवसाय पर दे रही है। जहां पर हमारे उद्यमी आ रहे हैं। नये नौजवान बच्चे आगे आ रहे हैं, but they had no help and directions. हमारे कैम्पस हरियाणा में लगते थे। हमने प्रावधान किया है कि उन कैम्पस को हम शिमला में भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उन कैम्पस को कांगड़ा, नूरपुर में लगा रहे हैं। हमारे बच्चों को वहां पर फ्री में प्रशिक्षण मिलेगा। 80 परसैंट

की ग्रांट-इन-ऐड आ रही है और आपको नज़र नहीं आ रहा है और आप कह रहे हैं कि ये उल्टी-पुल्टी स्कीमें हैं। आज पॉल्ट्री पर 60 परसैंट का हाइक मिल रहा है और आपने कह दिया कि आप तो युवाओं का बेवकूफ बना रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि दुकानदारी खोली है। अगर यंग एंटरप्रिन्योर्ज़ को तैयार करने का प्रयास हमारे मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? मैं बजट बुक की बात कर रहा हूं। आप उसका उद्देश्य समझिये। यह पहली सरकार है जो यंग एंटरप्रिन्योर्ज़ की मदद करना चाह रही है। वह हैल्प करना चाह रही है क्योंकि हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हम किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहते। न कभी हमने सरकारी नौकरी के बारे में बोला। सरकारी नौकरी बारे हमने कभी नहीं बोला। अन-इम्प्लॉईड एलाउंस के बारे में आपने बेवकूफ बनाया। नौकरियों के बारे में हमने कभी बेवकूफ नहीं बनाया। आज भी कांग्रेस पार्टी के पास एक केवल इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी का नाम है। वह बहुत महान् नेता थीं, इसमें कोई शक नहीं है। There is no doubt about that and nobody is questioning that. उसके बाद आपने क्या किया, वह भी सुनाया करो। आपकी लगातार यहां पर गवर्नमैंट्स रही हैं आपकी क्या ऐसी उपलब्धि है जिसके बारे में हिमाचल को हम कह सकते हैं। आपने टूरिज्म की बात कर दी। आज 50 करोड़ रुपया पहली बार प्रदान किया गया, आपने कितने पैसे दिए? आज आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार से बात की that he has a complete new vision and plans to develop tourism.

12.03.2018/1615/केएस/डीसी/1

हम तो आपसे यह एक्सपैक्ट करते हैं कि आप भी हमें सहयोग देते कि here are some of the points which should be considered. जो काम आपसे नहीं हो सका, अब यह सरकार करने जा रही है तो मैं यह एक्सपैक्ट करुंगा कि सब लोग एक कोऑर्डिनेशन का माहौल हिमाचल प्रदेश में पैदा करें। आशा जी, विपक्ष में रहकर आप केवल क्रिटिसिज्म करें for the hack of it, it is not called for. आज आप यहां पर इसीलिए हैं और जैसी भाषा का प्रयोग आपने पहले दिन से करना शुरू कर दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 15 साल तक भी आप यहीं रहेंगें।

अध्यक्ष महोदय, एक्साइज़ में गुंडा टैक्स क्या होता था ? 35 रुपये पेटी या 37 रुपये पेटी कहां जाती थी? यह कॉर्पोरेशन कहां से बन गई? एल-I, एल-डी का क्या खेल था? यह क्या नज़ारा था? आज कोई भी बेरोज़गार युवक पर्ची डाल सकता है। He can participate in the excise. बड़े-बड़े ग्रुप्स का पालन पोषण करके आपने एक्साइज़ का एक नया माफिया तैयार कर दिया। खनन माफिया तो था ही, वन माफिया तो था ही, ड्रग माफिया तो था ही लेकिन आपने इनके बाद एक्साइज़ माफिया भी हिमाचल प्रदेश में पैदा कर दिया। फिर आप कहते हैं कि कुछ नया नहीं है। एक्साइज़ पॉलिसी पढ़ी आपने? पंजाब में कांग्रेस की सरकार उसी दिशा में काम करना चाह रही है। आज कांग्रेस सरकार ने पंजाब में इस बात को माना, पंजाब क्योंकि हमारे बॉर्डर के साथ लगता राज्य है, उन्होंने माना कि जो हमारी पिछली पॉलिसी थी that was not good for the general masses. आपने शराब बेचने की बात की तो क्या आपकी सरकार शराब नहीं बेचती थी? कौन सी सरकार शराब नहीं बेचती या कौन सी सरकार बिना शराब बेचे सर्वाइव कर सकती है? केवल पोलिटिकल स्कोर फिट करने से इस प्रदेश का लाभ होने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा बजट आया है जिसमें आज एक जमींदार की सोच रखी गई। जमींदार के खेत को पानी लगे, इस बारे में बात की गई। आपने पोली हाउस के बारे में कहा । जहां आप उसके लिए 50 परसेंट देते थे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने फटे हुए पोली हाउस की शीट के लिए 70 परसेंट कर दिया, इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? अध्यक्ष महोदय, सोलर लाइट्स लगाने की बात

12.03.2018/1615/केएस/डीसी/2

कर रहे हैं, सोलर फैंसिंग की बात हो रही है। आज एग्रिकल्चर को प्रायोरिटी सैक्टर बना कर पेश किया गया। प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना में से 23 हजार करोड़ रुपया प्रदेश के अंदर आपके पास आ गया है , Sir, it is a welcome step or it is a backward step? आज इतना कुछ है। अध्यक्ष महोदय, आप घण्टी बजा रहे हैं लेकिन मैं एक घंटा इसके ऊपर और बोल सकता हूं। इतना कुछ है इस बजट बुक के अंदर और आदरणीय

मुख्य मंत्री जी ने अपने पहले बजट में एक बात साबित कर दी कि आने वाले पांच सालों में हिमाचल प्रदेश के अच्छे दिन आने वाले हैं। धन्यवाद।

12.03.2018/1615/केएस/डीसी/3

अध्यक्षः माननीय सदस्य डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल जी।

डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिलः अध्यक्ष महोदय, आपने बजट 2018-19 जो माननीय मुख्य मंत्री महेदय ने सदन में 9 मार्च, 2018 को प्रस्तुत किया था, उस पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। I must compliment our young Chief Minister Shri Jai Ram Thakur Ji for presenting his first Budget, you deserve all good. मान्यवर इससे पूर्व कि मैं बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दूं, मैं दो-तीन बिन्दू आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 2014 की जो हमारी लोकसभा की चुनावी सभाएं हुई थीं, उनमें मान्यवर नरेन्द्र मोदी जी द्वारा एक बहुत ही रंगीन वायदा हमारी भोली-भाली जनता को था और वह था कि हम सारा काल धन वापिस लाएंगें और सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपये जाएंगें but it never happened. यह हम सभी लोग जानते हैं लेकिन समय की भी कमी है so no need to elaborate. अच्छे दिनों की शुरूआत होगी, लोगों ने बहुत उत्सुकता से इसका भी इन्तज़ार किया।

12.3.2018/1620/av/hk/1

आज आप देख सकते हैं कि Maharastra Assembly is being encircled by more than fifty thousand framers. It speaks it all, it is something like a "Kissan long march". वह भी एक वायदा किया गया था कि एक ऐसा उपदान दिया जायेगा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर 50 प्रतिशत सब कृषकों को मिलेगा मगर कुछ नहीं मिला। मैं यहां पर एक और चीज कहना चाहता हूं जिसके लिए हम मान्य सदन में वर्ष 2004 तक पीछे जाएं जब दो प्रोमिनैंट नारे दिए गए थे। उसमें एक 'भारत उदय' और 'एकता इंडिया शाइनिंग'; The faith of both these slogans is known rest is history. इसके अलावा

एक और वादा किया गया था जिसमें माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि मैं आप सबका मुफ्त का चौकीदार हूं। मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा मगर इसके बिल्कुल विपरीत हुआ है। वे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, I think they were joking. अगर कोई पैक करके ले जाएं तो उसका मैं क्या कर सकता हूं। I think, it is a obvious reference to the recent PNB Bank scam in which many people like Shri Mehu Bhai Chowksi, Shri Nirav Bhai Modi and earlier Shri Lalit Modi Ji या ललित भाई मोदी कह दो, विजय भाई माल्या जी कह दो; इन सब लोगों ने वह धन जो लोगों ने अपने पास सचमुच में (---व्यवधान---) hold it, that is right in front of us. जो बड़ी मुश्किल से एक गृहिणी अपने पैसे रखती है वह सब बैंकों में गया और you know how it was stipend off to other countries. एक और बात कहना चाहूंगा these are the figures of Reserve Bank of India. They have given a data that the loans from PSU Banks taken is 61,260 crores over the last four years with recent addition of 11,400 crores by Nirav Modi Ji, the figures have touched 72,000 crores. Coincidently the same amount जो हमारी यू0पी0ए0 सरकार के समय में वर्ल्ड फेम्स इकोनोमिस्ट डॉ0 मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे और श्रीमती सोनिया गांधी जी यू0पी0ए0 की चेयरपर्सन थी उस समय इतनी ही 72 हजार करोड़ रुपये की धनराशि उन किसानों को माफ किया था जो आज हमारे देश को पोषण दे रहे हैं और जो हमारे सबके आधार है।

12.3.2018/1620/av/hk/2

Just a point in this August House. Now, coming down to the Budget. Before I tell you about these facts which I have told you about GST and demonetization, they will come down but really speaking, हमारे विपक्ष के नेता माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने बहुत ही अच्छे और विस्तृत शब्दों में कहा है कि किस प्रकार से योजनाओं के नाम बदले गये और it is something like the old wine put into a new bottle. I quote Thomes Sowell, who said, "Talkers are usually more

articulate than doers, since talk is their speciality." Now, we all know it that many things have been said, many things have been promised. मैंने पूरा बजट पढ़ा है लेकिन कुछ नया नजर नहीं आया। इसके 94 पृष्ठों के 160 पैराज में जो यह प्रस्तुत किया हुआ डाक्युमैंट है यह शब्दों और आंकड़ों का एक जाल है जिसको समेटकर हमारे सामने प्रस्तुतीकरण कर दिया गया है। Tell me where are those 2 crores jobs, which were promised by Shri Narender Modi Ji for our young population? Because of this people are so much desperate today which can easily be seen all over the country. एक लड़खड़ाती अर्थ-व्यवस्था। Our GDP has gone 2% down which make us scared.

12.3.2018/1625/TCV/HK-1

कर्नल धनी राम शांडिल ..... जारी

और जो बात हमारे विपक्ष के नेता ने कही कि हम इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? क्या उनका विवरण इस बज़ट में नहीं होना चाहिए था? हम इस राष्ट्र रूपी भवन को बनाते हैं, इसमें सभी लोगों का योगदान होता है। ये कोई अकेला व्यक्ति, कोई अकेली पार्टी या पार्टियों का समूह भी नहीं कर सकता है। ये एक प्रकार का महायज्ञ है, जिसमें सब की आहुति डलती है। इसलिए सभी को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे छः बार मुख्य मंत्री रहे, हमारे सीनियर लीडर राजा वीरभद्र सिंह जी यहां बैठें हैं। इन्होंने क्या कोई कम योगदान दिया। हिमाचल प्रदेश के निर्माता डा0 वाई0एस0 परमार, ठाकुर राम लाल, प्रो0 धूमल जी, श्री शांता कुमार जी इन सभी ने अपना-अपना योगदान दिया है। मैं समझता हूं कि उनका थोड़-सा रिफरेंस तो देना चाहिए था। हमारे से पूर्व जो मुख्य मंत्री रहे हैं, जिन्होंने प्रयास किया है कि हम जहां जिस मुकाम पर पहुंचे, राजा साहब बताते हैं कि ठियोग से आगे कभी जीप भी नहीं जाया करती थी, तो उस चीज को कहीं तो दर्शाना चाहिए था और उनका धन्यवाद करना चाहिए। श्री राकेश जी ने कहा था कि हम इंदिरा जी का नाम इतना क्यों लेते हैं? इनका नाम तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लिया था, उन्होंने तो इन्हें दूर्गा की संज्ञा दी थी। I was myself participating in all these battles, particularly in 1971, 1962 and

1965 also. उन्होंने जो इतिहास बनाया है, 93 thousand Pakistani soldiers laying down arms in Dhaka, is a unique example in the history of military. It is a golden page and we must remember it. What all she did, there is no time to discuss it because अध्यक्ष जी घण्टी दे देगें कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं। लेकिन मैं अपने समय का पाबंद रहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पैरा 54, 59, 60, 61 और 62 में पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण बारे में बड़ा सुन्दर लिखा है। मेरा मानना है कि पंचायती राज के 73वें संशोधन में जो राजीव जी कर गये हैं, वह एक अपने में इतिहास है। उसको भी बज़ट में मैंशन कर देना जरूरी था।

हमें स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी और उन सबके सपने साकार बनाकर अच्छे पंचायती राज के संदर्भ में बातें करनी चाहिए और आगे चलना चाहिए। श्री नरेद्र मोदी जी को मनरेगा का नाम शुरू में अच्छा नहीं लगा था। परन्तु धीरे-धीरे उन्हें अच्छा लगने लगा। Which is good. एक आकर्षक नाम दे देना, जैसे मैंने

12.3.2018/1625/TCV/HK-2

इस बज़ट के पैरा संख्या 59 में देखा है-'ग्राम गौरव पट्ट। यह बहुत अच्छी बात है। परन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे independent way में इस गौरव पट्ट को बनाये। क्योंकि इसमें परेशानी आती है कि किसको गौरव नहीं दिया। जहां तक कामों का ताल्लुक है, श्री वीरभद्र सिंह सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। I remember, as a Social Justice Minister, onetime increase of rupees one thousand was given to Aganbaries, which was the maximum of his time and in the history also. The Congress Government started Adarsh Balak / Balika Ashram in Mashobra, Tutikandi, Dhali and Sundernagar and also the Vridh Ashram in Basantpur. The Vridh Ashram of Basanput was also hailed by Ms. Nazma Hafidullah ji in Vigyan Bhawan in New Delhi. I remember when she heard that Raja Virbhardra Singh made it; she made a special mention of it. मैं राजा वीरभद्र सिंह जी, जो पूर्व में हमारे मुख्य मंत्री थे, हमारे रहनुम्मा थे और महामहिम राज्यपाल आचार्य देवब्रत दोनों

का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें रात-दिन बताया कि किस प्रकार से हम सोशल सैक्टर में आगे जा सकते हैं। I am sure my successor will do even better.

12-03-2018/1630/NS/YK/1

डा0 (कर्नल) धनी राम शांडिल----- जारी।

अध्यक्ष महोदय आप स्वयं विधायक रहें हैं और आप यह जानते हैं कि शामती बाईपास कितना जरूरी है। इसका थोड़ा सा काम रहता है। मैं इसके लिए आपका भी सहयोग लूंगा कि अगर वहां पर कोई समस्या है या ज़मीन में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हैं तो मैं और आप जायेंगे तथा उस समस्या का समाधान करेंगे। मेरे हिसाब से काम हमेशा आगे चलना चाहिए। इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीनियर सेकैंडरी स्कूल, कोटीध्योरा है there, work is also slow. Ongoing construction, जो चम्बा घाट का सर्किट हाउस है और कण्डाघाट का जो अस्पताल है, I think इनके लगभग आधे से ज्यादा काम हो चुका है। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये काम बंद नहीं होने चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र के पुलिस स्टेशन, सायरी की और दिलाना चाहूंगा। मैंने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए डी0जी0पी0 साहब से स्वयं रिपोर्ट लिखवा करके चार साल के प्रयत्न के बाद यह पुलिस थाना अनाउंस करवाया था। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी केबिनेट ने उसे डीनोटिफाई कर दिया है। I will request the Hon'ble Chief Minister to review this decision. I would go back to the days of Shri Ashwani Kumar Ji, what he used to do, वे पुलिस फोर्स की तरफ न जा करके थाने की तरफ जाते हैं। उन्हें ज्ञान था कि थाने का पैसा सैंट्रल फडिंग से मिलता है। Really speaking, Sir, the Police Station Sayri has its radius of about 65 km, there is no other police post. मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि manpower has not been revised I after 1971, you can see the statistics, कि किस प्रकार से ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं, ट्रैफिक ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं many other problems have come many other things have been put on the shoulders of the Police. So, the Police strength should improve and kindly do think over it that this Thana should be revived इसी प्रकार से दो-तीन प्वाईंट्स और हैं। उनमें से एक हरिद्वार बस का है। दूसरा, A small room for each MLA in any headquarter anywhere, may be in Dharmshala, Solan ,

Nahan. If we have mini secretariat it will be of use as all the States are following it. A request that Elected Representatives are never informed about the programs of the Government particularly of Chief Minister or any Minister. I think, we all are a team who must work together for the development of our area rather thinking that only a particular set of establishment will work. This is

12-03-2018/1630/NS/YK/2

my request. This is not the forum to tell minor administrative things which we keep on telling most of the time. Finally, before I conclude, I would like to touch upon one or two very sensitive issues. Why after 70 years of independence हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों को अलग कतार में बैठ करके खाना खाना पड़ता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी को बताना चाहूंगा कि यह ऐसी विडम्बना है पर यह सही है। I think, Dr. Ambedkar and Mahatama Gandhi उनको हम शर्मसार न करें it should have been mentioned somewhere in the Budget that we have a political will to stamp out such things मैं देख रहा हूं कि माननीय मोदी जी का वर्ष 2019 का टारगेट 2022 में न चला जाये। मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा न हो। जो उद्देश्य आपने रखे हैं, इसमें माननीय मुकेश जी ने ठीक कहा है कि how do we really cater for the deficit? It is very simple economic question. Very difficult how do we cater? Resource mobilization is very important. Respect of the armed forces is necessary; I am referring to the Jantar Mantar, Col. Inder Singh Ji is also here with me. The treatment given to the forces was not up to the mark. It was not expected from the Government of the day. Here in Dharamshala, we have made a very good war memorial which is top in the country. My request is to the Hon'ble Chief Minister that it should be properly managed and looked after as it is made. No Jumlas will work now.

12.03.2018/1635/RKS/YK-1

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल...जारी ।

कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जैसे बुद्धि आ गई है। As you know the allies are falling apart. Why can't we? As this August House knows that we Himachalies will give a different sort of performance as far as communal harm is concerned, और खुशी की बात यह है कि ऐसा हुआ भी नहीं है। परन्तु मैं चाहूंगा कि हम इकबाल की उस बात को याद रखें। उन्होंने कहा था -

'मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
हिन्दी हैं, हम वतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा।
सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा।

हम समझते हैं कि इस गुलिस्तां को हम हमेशा महक से भरा रखें ताकि ये हमारी आज़ादी को महफूज रखे। हम ऐसा काम करें जैसे सन् 1962, 1965 और सन् 1971 में हमारे देशवासियों ने किया था। They always came up for expectation young people should be away from the किसी भी प्रकार जो नशा या उल्टी-सीधी चीजें होती हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हमें कभी भी ऐसी चीजें अपने युवाओं को नहीं बतानी चाहिए। अगर हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते हैं तो एक अच्छी गाइडैंस तो दे ही सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, there, comes the time in the history of any nation and in our country it has already come. We must protect our nation from any fiscal pendencies and any communal disturbances from anything which is against us. Our identity is not that I am from Nurpur, I am from Solan or from Rampur. Our identity is that we are Indians. With these words. जैसे हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री मुकेश जी ने कहा कि इस बार का बज़ट दिशाहीन है। यह बजट वास्तविकता से परे था। इस बज़ट में काल्पनिकता ज्यादा थी और यह तथ्य रहित था। मैं समझता हूं कि now the young Chief Minister with his vibrant team of young Ministers will be able to

12.03.2018/1635/RKS/YK-2

give us a very good Budget next time than I will think of supporting him. Jai Hind, Jai Bharat, Thank You Sir.

अध्यक्षः अगले वक्ता मानीय श्री रमेश चन्द ध्वाला जी चर्चा में भाग लेगें।

श्री रमेश चंद ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने पेश किया है यह बजट लगभग 46 हजार 385 करोड़ रुपये के कर्ज में जकड़े हुए हिमाचल प्रदेश का बजट है। वर्षों बाद इस बज़ट में कुछ नया दिखाई दे रहा है। सभी समाज के वर्गों को ध्यान में रखते हुए विशेषकर जो नौजवान हैं, उनको अपने पैरों में खड़ा करने के लिए और किसानों के हित के लिए इस बजट में काफी कुछ दिखाई दे रहा है। परन्तु किसी की दृष्टि काम न करें तो वह सृष्टि दिखाई नहीं देती है।

12.03.2018/1640/बी0एस0/ए0जी0-1

लेकिन मैं यह कहने जा रहा हूं कि जिस तरीके से हर चीज को टच किया हुआ है। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने भी इस बजट की सराहना की है प्रशंसा की है कि इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर वर्ग को छुआ है। लेकिन विरोध करना इनकी मजबूरी है। कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि बजट तो बहुत बढ़िया है परंतु नम्बर तो 5 ही देंगे। अब ये अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। अब इनका जो धर्म है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं वहां एक बात सुनाने जा रहा हूं। एक व्यक्ति ने अपने घर में गृह प्रवेश रखा। उनका एक पड़ोसी था, वह अनाप-शनाप ब्यानबाजी करता था। उसने कहा कि मैं इस व्यक्ति को अपने घर गृह प्रवेश में नहीं बुलाऊंगा। यह बत्तमीज आदमी है। फिर पड़ोसियों ने कहा कि बुला लो, आखिर पड़ोसी-पड़ोसी होता है। फिर उनके कहने पर उसको बुला लिया। जब बुला लिया गया तो सभी लोंगो ने नए घर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि बहुत अच्छा मकान बना है, इसकी खिड़कियां बहुत अच्छी है, इसकी फ्लोरिंग बहुत अच्छी है, इसकी अलमारियां बहुत अच्छी है। हर चीज की प्रशंसा की । जब उसके पड़ोसी की

बारी आई तो उसने कहा वैसे तो मकान बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका दरवाजा छोटा है। उन्होंने कहा कि ठीक है इसका दरवाजा बड़ा कर लेंगे। बोले वह आपकी मर्जी है लेकिन अगर अर्थी निकालनी पड़े तो दिक्कत हो जाती है। अध्यक्ष जी, जिन्होंने बुरा ही कहना है उनका कुछ नहीं किया जा सकता। विपक्ष वाले अपना धर्म निभा रहे हैं । हमारे मित्रों का यह हाल है "आप करें तो सैर हम करे तो आवारागर्दी" । उसमें हम कुछ नहीं कह सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं शिक्षा विभाग से शुरू करना चाहूंगा, शिक्षा पर सरकार ने 7 हजार 46 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा जो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। पूर्व सरकार में जो इन्होंने कांटे डाले हैं उसका भी निराकरण

12.03.2018/1640/बी0एस0/ए0जी0-2

उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए

कीजिए। We shall appreciate your betterment. इतना बुरा हाल शिक्षा विभाग का किया है। 3-3 बच्चों के लिए स्कूल है। एक अध्यापिका एक बच्चे को पढ़ा रही है, मैंने कहा कि आप नीचे क्यों नहीं बैठती हैं? बोली मुझे शर्म आती है। This will be great insult of me. वहां पर चार बच्चे, चार अध्यापक । एक आज अध्यापक के ऑर्डर हुए, उसको मैं पूछ रहा था कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं ? शिमला का ही स्कूल है । उस स्कूल में पिछले साल पहले चार अध्यापक थे और एक बच्चा पढ़ाई करता था और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वह बिहारियों और गोरखों के बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे इन अध्यापकों की वजह से प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और उस स्कूल का नाम है राजकी माध्यमिक पाठशाला गुजारन (ढली) । इस नाम से यह स्कूल है। वहां चार बच्चे है, पांच वहां अध्यापक और एक सेवादार है। आज ये लोग फिजूलखर्ची की बात कर रहे हैं। फिजूलखर्ची किसने बढ़ाई? एक-एक पंचायत में 7-7 स्कूल हैं और उन स्कूलों में 4, 5 और 11 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इन स्कूलों को क्लब कीजिए। जहां पांच

अध्यापक है वहां बच्चो की संख्या भी बढ़नी चाहिए। सरकार ने काफी बजट का प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में किया है। सरकार जो भी तरीका, या पॉलिसी बनाना चाहती है, सरकार बनाए। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू करवाईए, तब जा करके सरकारी स्कूलों में संख्या बढ़ेगी और बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाने से रूकेंगे। वरना मैं यह कह रहा हूं कि अगर स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो जो अध्यापक सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, वे किसे पढ़ाएंगे ?

12.03.2018/1645/DT/AG/1

श्री रमेश चंद ध्वाला -----जारी।

कई स्कूलों में तीन बच्चे और तीन ही टीचर्ज़ हैं। आठ स्कूल ऐसे हैं जिनमें आठ बच्चों से कम संख्या है और वहां पर चार टीचर्ज़ हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह फिज़ूखर्ची किसने की है? मेरे विधान सभा क्षेत्र में 60 स्कूल अपग्रेड किये गये हैं और नौ-नौ बच्चों की संख्या वाला स्कूल भी हाई स्कूल है। Who will pay all the expenses? मेरे हिसाब से यदि उन बच्चों को अमरीका भेज दिया जाता तब भी वे विद्यार्थी पढ़ जाते। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने यह सब वोट की राजनीति के लिए किया है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर अगर आपने कोई समीक्षा नहीं की, कोई नीति नहीं बनाई तो ये स्कूल बंद हो जायेंगे। बी0पी0एल0 परिवारों के लोग भी अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं। पिछली सरकार ने जो रेवड़ियों की तरह स्कूल बांटे हैं, आप इसके ऊपर समीक्षा कीजिए। आप हमें कह रहे हैं कि फिजूलखर्चे वाला बजट है। हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। You are hereby invited. आप बैठिये और जो फिजूलखर्ची है उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए। जहां पर कोई अंकुश लग सकता है तो वहां पर अंकुश लगना चाहिए। प्रदेश के ऊपर जो इतना कर्ज़ा है इसके ऊपर कोई न कोई राईडर लगना चाहिए। लेकिन उसके लिए आप (विपक्ष) तैयार नहीं होगें, आप यह सोचेंगे कि हम इनको डिफेम कैसे करें? आपने कोई भी काम योजनाबद्ध ढंग से नहीं किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी सरकार के समय हजारों लोगों को

सेवा विस्तार दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने जिस व्यक्ति को अढ़ाई साल का सेवा विस्तार दिया था, उसने मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 480 शिलान्यास और भूमि पूजन तथा उद्घाटन करवाये हैं और इसके लिए बजट में राशि का प्रोवीज़न एक हज़ार का किया गया था लेकिन वहां पर उद्घाटन पट्टिका पर उस परियोजना के लिए लगभग 78

12.03.2018/1645/DT/AG/2

लाख रुपये की राशि दर्शायी गई है। इस तरीके की फिजूलखर्ची को रोकने की आवश्यकता है। आपने वहां पर जितने शिलान्यास, उद्घाटन और भूमि पूजन किये हैं उस राशि से कम-से-कम दो सड़कें बन सकती थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आप पूरी समीक्षा कीजिए। यह स्वयं (विपक्ष) कहते थे कि अंग्रेजों के समय से लोग प्रशंसा करते थे कि हिमाचल प्रदेश की शिक्षा सबसे सुदृढ़ है। आपने वर्ष 2004 में ऐसी नीति बनाई कि बच्चा पढ़े या न पढ़े उसको पास कर दिया जाये। मुझे आशा है कि हमारी सरकार इसके बारे में विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, वह बच्चा भविष्य में क्या बनेगा जो सौ तक गिनती नहीं सुना सकता है। आपने रेवड़ियों की तरह तो स्कूल दे दिये हैं। ऐसा कहा जाता है कि Education is backbone of every country. यह क्या हो रहा है? ये सारे के सारे स्कूल बंद हो जायेंगे। आप हमेशा नुक्ताचीनी न करें, आप अच्छे काम के लिए भी मदद कीजिए। सरकार बने हुए अभी दो महीने का ही समय हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या दो महीने का बच्चा पलटी मारने शुरू कर देता है? आप मुख्य मंत्री महोदय से दो महीने का हिसाब पूछ रहे हैं। आपको यह लग रहा है कि हम वहां कैसे पहुंचे? आपकी नैय्या ऊपर से ही डूबने वाली है, आप क्या कर सकते हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैंने मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री जी से भी बात की है। प्रदेश की सड़कों की हालत दयनीय है। सड़कों की इतनी दुर्गति है कि जो पैरापिटस लगने चाहिए थे, वे लगाये ही नहीं गये हैं। वहां से 70-70 किलोमीटर से बज़री उठा करके रातों रात चेहतें ठेकेदारों ने ऐसा काम किया है।

श्री रमेश चंद धवाला ... जारी

मैंने तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कहा कि वहां के लिए कोई पैसा न दिया जाए। आज वह सारी-की-सारी सड़कें खड्डें बनी हुई हैं। यह करोड़ों रुपया कहां से आता है? लोगों के ऊपर टैक्स लगता है और यह पैसे जी.एस.टी. आदि के माध्यम से लोगों से वसूल किए जाते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि ऐसी सड़कों के लिए कोई-न-कोई मापदंड तो होना चाहिए। पहले विभाग वहां जाकर देखे कि अगर वहां पर वॉटर लॉग्ड एरिया है तो वहां पर सी.सी. कंक्रीट का काम जाए और जहां पर ठीक है वहां के लिए कम-से-कम लैबोरेटरी में चैकिंग तो हो। वहां ऐसा कोई नहीं कर रहा। इस काम के लिए वहां कोई होता ही नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि जो बीत गई, सो बात गई, आगे के लिए हम बढ़िया काम करेंगे ताकि कोई आदमी हमारे काम पर उंगली न उठा सके। उसमें चैकिंग हो और जहां-जहां जिस चीज़ की ज़रूरत है वह वहां हो। अब जो बड़े-बड़े प्रोजैक्ट हैं वहां पर तो बड़ी लेबर काम कर रही हैं लेकिन जो छोटी सड़कें हैं, जो किलोमीटर या 2 किलोमीटर लंबी हैं, वहां पर भी बड़े-बड़े ठेकेदार आ रहे हैं। जो सड़कें नवम्बर महीने में बनी हैं अब वह खड्डें बन चुकी हैं। इसलिए यह सारा काम हमारी सरकार सुधारेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ग्रास रूट के व्यक्ति हैं; किसान हैं। तभी तो कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा है कि एक किसान का बेटा मुख्य मंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठा है। ...(व्यवधान)... आप बैठे रहो, किसान ये हैं आप नहीं हैं।

मैं कहूंगा कि आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैंने कई बार यहां विधान सभा में कहा है कि ठीक है कि डैमोक्रेसी में मधुमक्खी के छत्ते से थोड़ा-बहुत शहद हाथ में लग जाए; हालांकि मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, हम भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर वह शहद लगा हाथ चाट लिया जाए, इतना तो डैमोक्रेसी में चल सकता है। लेकिन जिन्होंने छत्ता भी खाया, मधुमक्खियां भी खाई और शहद भी खाया, तो फिर बचा क्या? फिर आप यहां पर

मंदिरों की बात कर रहे हैं? पूर्व मुख्य मंत्री चले गए। पौने दो करोड़ रुपया मुख्य मंत्री राहत कोष से ज्वालामुखी से दिया गया है। वहां पर कोई क्राईटेरिया नहीं देखा गया। जबकि यह नार्मज बने हुए हैं, सरकार की पॉलिसी बनी हुई है कि कोई भी टैंडर ऑन लाईन ही होगा। लेकिन वहां ऑन लाईन न करवा कर ऑफ लाईन टैंडर करवाए गए हैं और दुगुनी दरों पर वह करोड़ों के काम दिए गए हैं। वहां पर कॉलेज में 6 करोड़ रुपया लगा है जबकि अभी 50 लाख रुपया उसमें और लगेगा। वहां टैंडर में बहुत ज्यादा रेट डाले गए हैं। इसका क्या तरीका था? क्या डी.सी. या एस.डी.एम. को इसकी पॉवर थी? मतलब वहां कोई कायदा-कानून माना ही नहीं गया। उसमें कोई टैक्निकल सैंक्शन नहीं थी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं थी और कोई स्पलिट-अप करने की अप्रूवल भी नहीं है। उसमें करोड़ों रुपया उन लोगों ने खाया है। वहां पर लगभग 15-16 करोड़ रुपये के काम हुए हैं जबकि पॉलिसी और कानून यह है कि डी.सी. की पॉवर 10 लाख रुपये तक है और एस.डी.एम. की पॉवर केवल एक लाख रुपय तक की है। फिर यह करोड़ों रुपये के काम कैसे हो गए? जो वहां पर एस.डी.ओ. या तहसीलदार बैठे हैं, किसी से कुछ नहीं पूछा गया जबकि सारे मंदिरों में ऐसा हो रहा है। इतनी पिलफिरेज़, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं यह कहूंगा कि सारे कायदे-कानूनों को ताक पर रखकर ऐसे काम किए गए।

मैं हॉस्पिटल की बात माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से भी कह चुका हूं कि वहां पर जो हॉस्पिटल की 17 कैनाल ज़मीन थी उसको ट्रांसफर करके वह सैक्रेटरिएट के नाम कर दी गई। जो ऊपर ज़मीन थी वह मंदिर ट्रस्ट की थी। वहां उस ज़मीन को ट्रांसफर किया गया। क्या ऐसी नीति है? अगर है तो कोई आई.ए.एस. अधिकारी मुझे बताए कि क्या ऐसी नीति है? मंदिरों की ज़मीन कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। मंदिर की ज़मीन ट्रांसफर करके वहां का हॉस्पिटल एक सरायें में चल रहा है। वहां इस तरीके से मनमाने ढंग से काम किया गया है। कानून किसी का मित्र नहीं है। वह मेरे लिए भी है और किसी दूसरे के लिए भी है।

12/03/2018/1655/RG/DC/1

श्री रमेश चंद ध्वाला-----जारी

तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे काम किए गए हैं। मैं इनके क्या-क्या काम गिनाऊं, यदि गिनाऊंगा, तो एक घण्टा लग जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा कृषि की बात करता हूं। इसमें बजट में काफी कुछ किया गया है। आज लोग कृषि का धन्धा छोड़ने की कगार पर हैं, इसको कोई नहीं करना चाहता। क्योंकि सब कुछ जंगली जानवर खा जाते हैं, बंदर और सूअर फसलों को खा जाते हैं। इसलिए इस व्यवसाय को कोई नहीं करना चाहता। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी की जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। इन्होंने बजट में खेतों की बाड़बंदी करने के लिए 85% सब्सीडी की घोषणा की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गुजरात में देखा कि उस बाड़ में करेंट है और जानवर वापस चले जाते हैं। क्या इस तरह की सोच कोई गलत है? मैंने सौर ऊर्जा का कन्सैप्ट गुजरात में देखा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि श्वेत-पत्र जारी किया जाए कि इन्होंने किस-किस जिले में कितने-कितने लोगों को नौकरी दी है? मैं कहना चाहूंगा कि युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कोई उद्योग लगाएं या उनको कोई काम-धंधा देंगे तभी वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यहां लोक निर्माण विभाग वालों को मैंने कहा कि वहां ऐसा कन्सैप्ट है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से सड़क के पानी को इकट्ठा करके लोगों के खेतों तक ड्रिप इरीगेशन के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। युवा बेरोजगार वहां बिजली के प्रोजैक्ट्स लगा रहे हैं। ये अपने कार्यकाल में बताएं कि दो और पांच मेगावाट के कितने प्रोजैक्ट्स स्वीकृत हुए? इनकी फार्मल्टीज इतनी कर दी हैं कि पॉवर ट्रांसमीशन तक कम-से-कम पचास करोड़ रुपये खर्च हो जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से भी गुजारिश करुंगा कि इसका सरलीकरण किया जाए। यहां पर भी सौर ऊर्जा के प्रोजैक्ट्स यहां के युवा बेरोजगारों को दिए जाएं ताकि उनको कोई काम-धंधा मिले। अब 4500 करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट भारत सरकार दे रही है और भारत सरकार इसमें इतनी सहायता कर रही है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी प्रोजैक्ट के लिए यदि 500 करोड़ रुपया आया, तो अधिकारी उसको भी खर्च नहीं कर सके। उस प्रोजैक्ट की डी.पी.आर. नहीं बना सके। वह सारा-का-सारा पैसा वापस चला गया। यह सारी सरकार और अधिकारियों की

गलती है कि वह पैसे क्यों वापस गए? इसलिए मेरा कहना यह है कि भारत सरकार से आए हुए पैसों का सदुपयोग करना चाहिए।

12/03/2018/1655/RG/DC/2

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस बजट में ऐसा प्रबन्ध भी किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग के लिए लगभग 22,000 सेल-सेन्टर्ज बनाए जाएंगे। इसलिए यदि हम अपने युवा बेरोजगारों के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, तो कैसे काम चलेगा? ये बच्चे पहले आपके नारे लगाते थे, अब हमारे नारे लगाएंगे। लेकिन इन बच्चों की चिन्ता कौन करेगा?--(घण्टी)---मैं कहता हूं कि एक दिन या दो दिन बैठकर इसकी समीक्षा करो कि हम इन बच्चों को कैसे रोजगार दिला सकते हैं। इसलिए आपको माइलेज ऐसे ही नहीं मिलेगा। अब उन्होंने सभी को देख लिया है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो पैसा भारत सरकार से आ रहा है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसका ठीक प्रकार से और पारदर्शिता के साथ सदुपयोग होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री महोदय बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय पानी की कमी होने वाली है क्योंकि वाटर लेवल डॉऊन होता जा रहा है। इसमें सर्वाइवल हो सकती है, मैंने अपने क्षेत्र में इसको किया है, वहां डैम बनाए।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रमेश चन्द ध्वाला : डैम बनाने से वहां हमारे ट्रैडीशनल सोर्सिज भी रिवाइव हो रहे हैं, उनमें भी पानी आ रहा है। इस तरह की सोच रखनी होगी। इस प्रकार ग्रेविटी से या चैक डैम लगाकर हमारे खेतों तक वह पानी जाए। सौर ऊर्जा का पैनल लगाकर आपके खेतों तक अपने आप ही पानी चला जाएगा। मैंने देखा है। इस प्रकार यदि हम योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, तो लोग सरकार के कार्य की प्रशंसा करेंगे। तो इन्होंने जो किया है, इन्होंने तो क्या किया, क्या नहीं किया,

अगर मैं सारी बातें आपको बताऊं तो आप और ऊंचे उठेंगे। इसलिए जो हम जन-प्रतिनिधि हैं उन्हें देखना चाहिए कि अगर किसी गांव में ऐसी व्यवस्था हो जाए तो क्या मुख्य मंत्री जी ने बुरा किया? -(व्यवधान)-वह आपके क्षेत्र में बनेगा, हमारे क्षेत्र में थोड़े ही बनेगा। -(व्यवधान)- सबके चुनाव क्षेत्रों में बनेगा।-(व्यवधान)-तो बाकी बातों के लिए भी समर्थन दो। उसमें आप उतावले क्यों हो रहे हैं?

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हम जन-प्रतिनिधि अगर मिलकर कोई काम योजनाबद्ध ढंग से लोगों के लिए करेंगे तो लोग खुश होंगे। आप लोगों ने सारा कुछ राजनीतिक दवाब के कारण गलत किया है। अगर आप लोग सिस्टेमेटिकली कोई काम करेंगे तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और अगर गलत काम करेंगे तो लोग बुरा बोलेंगे।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः अभी तो गाड़ी चली ही है। अभी पांच मिनट और लगेंगे।-(व्यवधान)- आप जो यहां वोल्वो बसिज की बात कर रहे हैं। वोल्वो बसिज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं सब-कुछ जानता हूं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए। अभी तीन और माननीय सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः मैं समाप्त ही कर रहा हूं। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, यह बात पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों तक जानी चाहिए कि यह मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और दुकानदारों के लिए सबसे बढ़िया बजट है लेकिन यहां पर कुछेक कह रहे हैं कि इस बजट में नुक्स है। मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि दो दिन की एक कार्यशाला रखी जाए क्योंकि कई अफसर

डेढ़ से दो लाख रुपये तनख्वाह लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं। होना यह चाहिए कि जो उस विभाग का हैड है उसको पूछा जाना चाहिए कि आपके अण्डर जो स्टाफ है इनकी

12/03/2018/1700/MS/AG/2

कार्यशैली कैसी है, ऐसी बातों पर चर्चा होनी चाहिए। अब सड़कों पर जो कुछ हो रहा है क्या उसको हम देख नहीं रहे हैं? हम सबकुछ देख रहे हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः उपाध्यक्ष जी, किसी और के पांच मिनट ले लेना।

उपाध्यक्षः कौन पांच मिनट आपको दे रहा है? जो आपको पांच मिनट दे रहा है उस सदस्य का आप नाम लिखवा दें, मैं नोट कर लेता हूं।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः उपाध्यक्ष जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं तो ठीक है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्षः यह सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। अभी तीन अन्य माननीय सदस्यों ने भी बोलना है। -(व्यवधान)- ऐसा है हम आपकी भावनाओं की भी कद्र करते हैं और आपकी उम्र की भी कद्र करते हैं।

अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह रायजादा जी भाग लेंगे।

12/03/2018/1700/MS/AG/3

श्री सतपाल सिंह रायजादाः उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 9 मार्च को जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में बजट पेश किया है, उस पर चर्चा हेतु समय दिया, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, मैं पहली बार विधान सभा में चुनकर आया हूं और पहली ही बार मुझे यहां अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला है। मुझे सदन के तौर-तरीकों के बारे में

थोड़ा कम ही ज्ञान है इसलिए अगर किसी कारणवश मुझसे बोलने में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें।

उपाध्यक्ष जी, वर्तमान के मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने जो आम बजट पेश किया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं।

12.03.2018/1705/जेके/एचके/1

श्री सतपाल सिंह रायज़ादाः-------जारी-------

उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में हुए चुनावों से पूर्व भाजपा द्वारा प्रदेश की जनता को जो दृष्टिपत्र के माध्यम से प्रलोभन दिए गए वह एक भी वायदा इस बजट से पूरा हुआ दिखाई नहीं देता। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने बजट में विधायक निधि में 15 लाख बढ़ाने का वायदा किया, जिसका मैं स्वागत करता हूं। हमें इनसे उम्मीद थी कि यह 1 करोड़ 50 लाख तक होना चाहिए था, फिर भी मैं 15 लाख रूपया बढ़ाने के लिए इनका स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्षः मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं इसलिए कृपया शांत रहें।

श्री सतपाल सिंह रायज़ादाः उपाध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के बागवानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक से 1134 करोड़ रूपए स्वीकृत करवाए गए थे, जिसकी अब प्रदेश सरकार झूठी वाहवाही लूटने जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का जब भी गहन अध्ययन करोगे तो उसमें पर्यटन क्षेत्र में बजट का कोई ज्यादा प्रावधान नहीं किया गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्र में एन0डी0ए0 सरकार के पिछले चार वर्षों में देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के साथ केन्द्र सरकार ने सौतेला व्यवहार किया। ऊना जिला में पिछली प्रदेश सरकार ने आते ही स्वां प्रोजैक्ट के लिए 922 करोड़ रूपए मंजूर किए थे और उस वक्त केन्द्र में कांग्रेस सरकार थी और दो साल कार्य बहुत तेजी से चला, इस परियोजना में 418 करोड़ रूपए

खर्च किए गए, जिसमें भारत सरकार द्वारा 214 करोड़ रूपए जारी किए गए तथा शेष 174 करोड़ रूपए राज्य सरकार द्वारा दिए गए। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों से जब से केन्द्र में भाजपा सरकार आई तब से यह बन्द पड़ा है। मैं, मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आने वाले दिनों में वह कार्य दोबारा से शुरू होगा, जो प्रोजैक्ट बीच में खड़ा हो गया है और बीच में ही पूरा नहीं हो पाया है। कई ऐसे प्रोजैक्ट है जो बीच में रह चुके हैं वे आगे पूरे नहीं हो पाते हैं इसलिए क्या अब

12.03.2018/1705/जेके/एचके/2

वह प्रोजैक्ट पूरा हो जाएगा? अब इस परियोजना में जो पैसा आना था वह भी बन्द हो गया है और अब यह परियोजना बन्द पड़ी है। यह भेदभाव नहीं है तो क्या है? राज्य में जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तब से तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया। जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को विकास के लिए 90 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता था। जब एन0डी0ए0 सरकार आई उस समय लगभग तीन साल के लिए इस अनुदान को बन्द कर दिया गया था। जिससे कई हजार, करोड़ रूपए का नुकसान प्रदेश सरकार को उठाना पड़ा था। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय एन.डी.ए. सरकार द्वारा प्रदेश में घोषित 69 एन0एच0 का मामला भी केन्द्र सरकार में भाजपा सरकार ने उलझा रखा था। मैं अपने क्षेत्र ऊना के बारे में एक बात जरूर कहूंगा जो ऊना-संदोगढ़ सड़क है उसकी हालत बहुत खस्ता है। पीछे काफी समय से क्योंकि यह सड़क भी अब एन0एच0 में आ गई है, इसमें न तो एन0 एच0 का काम चल रहा है और न ही प्रदेश सरकार उसमें कोई कार्य करवा रही है। मेरा विधान सभा क्षेत्र

12.03.2018/1710/SS-YK/1

श्री सतपाल सिंह रायजादा क्रमागतः

पंजाब के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण जो साथ लगते गांव हैं वहां पर कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर हिमाचल की बिजली नहीं मिलती है। उनके राशनकार्डस वोटरकार्डस सारे

हिमाचल के हैं और अब तो पंजाब गवर्नमैंट ने भी यह बोल दिया है और वे एन0ओ0सी0 नहीं दे रहे हैं। इसलिए आगे जो मकान बना रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। मेरी मुख्य मंत्री जी से गुजारिश रहेगी कि वे इस ओर भी ध्यान देंगे। महोदय, आपसे मैं एक बात यह भी बोलना चाहूंगा कि रेलवे लाइन जो ऊना-तलवाड़ा जाती है वहां पर एक कोढ़ी आश्रम था उसको डेढ़ साल पहले तोड़ दिया गया क्योंकि वह उनकी जगह में था। तो उसके बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी ने वहां के डी0सी0 को आदेश दिए थे कि एक अच्छी जगह देखकर इनके आश्रम को बनाया जाए। अभी 15 दिन पहले मैंने डी0सी0 साहब से बात की। एक्चुअली वह जगह कोढ़ आश्रम को एलॉट भी करवाई गई थी, जो हमारे यहां पर मंत्री जी हैं इनकी कांस्टीचुऐंसी से आते हैं वहां पर एलॉट करवाई गई जोकि मेरे बॉर्डर पर पड़ता है। लेकिन डी0सी0 ने अचानक उन कोढ़ियों की जगह रद्द कर दी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि यह जगह उनके लिए एलॉट ही नहीं हुई। जबकि यह जगह उनको एलॉट भी हुई और डी0सी0 साहब ने इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूंगा कि सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद आस्था भी बदलती है। यह सही बात है लेकिन जो कोढ़ी है या दबा-कुचला समाज है उनके लिए आस्था नहीं बदलना चाहिए, हमारे लिए बदल जाए तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही हमारे वहां अभी परसों का एक केस है जिसमें दो दिन हो गए लेकिन पुलिस डिपार्टमैंट ने केस दर्ज तक नहीं किया। आज मैंने आते-आते बात की तब जाकर एस0पी0 साहब ने भरोसा दिया कि केस दर्ज होगा। वह व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट था लेकिन दो दिन बाद तक केस दर्ज नहीं हुआ। महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहूंगा कि पीछे हमारे मंत्री महोदय कुटलैहड़ से कंवर साहब और सांसद महोदय, अनुराग जी ने एक हॉस्पिटल में डायलेसिज़ यूनिट का उद्घाटन किया तो वहां पर एक पट्टिका के नीचे सतपाल सिंह सत्ती जी का भी नाम दिया गया। मुझे नहीं पता कि वहां पर प्रदेशाध्यक्ष का नाम होता है या नहीं। वैसे तो आप जितने मर्जी उद्घाटन करो, साथ में चाहे पूरे प्रदेश में जितने भी इनके कैंडीडेट्स

12.03.2018/1710/SS-YK/2

हैं उनका नाम लिखवा दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कोई-न-कोई सिस्टम होता होगा। कुछ-न-कुछ बात होती होगी, वह आपने देखना है। अगर नाम लिख सकते हों तो

लिखते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमें थोड़ा-सा ज्ञान ज़रूर दे दें कि वहां पर ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता। --(व्यवधान)-- फिलहाल मैं बोल रहा हूं। उतनी देर मैंने कुछ नहीं बोला, जब आप बोल रहे थे। आपके बीच में पहली दफा बोल रहा हूं। अगर मैं गलत भी हूं तब भी माफी चाहता हूं।

उपाध्यक्षः सतपाल जी, आप बोलिये। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं।

श्री सतपाल सिंह रायजादाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे यही दरख्वासत रहेगी कि यह सरकार गरीबों की तरफ ज्यादा सोचे। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी ने शेरों-शायरी में लास्ट में बोला था कि *सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत भी बदलनी चाहिए।* लेकिन सूरत तब बदलेगी जब कोई गरीब हॉस्पिटल में जाता है तो उसको वहां पर फोन करने की ज़रूरत न पड़े। सूरत तब बदलेगी अगर कोई व्यक्ति तहसीलदार ऑफिस अपना एस0सी0, ओ0बी0सी0 इत्यादि सर्टिफिकेट बनाने जाता है तो वह दस या पंद्रह दिन बाद न बने बल्कि उसी वक्त बने या दूसरे दिन बने, इसकी जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए। जब तक इसके ऊपर हम लगाम नहीं लगायेंगे तब तक सूरत नहीं बदलेगी। अब मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर फिर भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहूंगा। जय हिन्द, जय भारत।
12.03.2018/1715/केएस/वाईके/1

उपाध्यक्षः अब इस बजट चर्चा में भाग लेने के लिए मैं कर्नल इन्द्र सिंह जी से आग्रह करता हूं।

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 के लिए जो बजट अनुमान माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय सदन में रखें हैं, उन पर चर्चा के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक ऐतिहासिक बजट, सर्वहित बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं और साथ में मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने एक नई सोच के साथ, लकीर से हटकर एक बहुत बढ़िया, चमत्कारी बजट इस

प्रदेश को दिया है जिसमें समाज के हर वर्ग के हित का ध्यान रखा गया है। हां, इसको समझने के लिए सोच बदलने की जरूरत है। अगर हम प्रीकन्सीव्ड आइडिया से इसका आकलन करें तो सही आकलन नहीं होगा जैसा कि सुबह ही कांग्रेस पार्टी के लीडर ने इस बजट को बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया।

उपाध्यक्ष महोदय, 1948 में जब इस प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय यह प्रदेश फाइनैंशियली वाइबल स्टेट नहीं था। हमारी इकॉनमी मनिऑर्डर इकॉनमी थी। यह सोचने का विषय है कि गठन के बाद भी लम्बे अरसे तक किस पार्टी ने इस प्रदेश में राज किया? एक छत्र राज इस प्रदेश में किसका रहा? आज जो मौजूदा फाइनैंशियल क्राइसिज़ प्रदेश फेस कर रहा है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। आपने सोर्स मोबलाइजेशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं जिसकी वजह से आज हम आर्थिक संकट की स्थिति में है। टूरिज्म और हाइड्रो पावर जो इस प्रदेश के मेन दुधारू सैक्टर्ज़ हैं, उनका पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया। सरकारें ऋण पर ऋण लेती रहीं। आज प्रदेश में जो कर्जा है वह 46, 385 करोड़ है। आपका टोटल ले आउट 41,440 करोड़ है जो सरकार पूरे साल में खर्च करेगी। इससे भी ज्यादा आपके ऊपर कर्जा है जिसके लिए कहीं न कहीं सामने बैठी हुई कांग्रेस सरकार उत्तरदायी है। मैं थोड़ी सी तुलना करना चाहता हूं। बी0जे0पी0 के पांच साल के शासन 2007 से लेकर 2012 तक 7,621 करोड़ का ऋण सरकार ने लिया

12.03.2018/1715/केएस/वाईके/2

लेकिन इसके विपरीत पांच साल के शासन में वर्ष 2012 से 2017 तक कांग्रेस पार्टी के शासन में 18,787 करोड़ का कर्जा लिया गया। यानि दोनों सरकारों की तुलना करें तो कांग्रेस ने इन पांच सालों में 11,166 करोड़ रुपया ज्यादा कर्जा लिया। सरकार वह भी चल रही थी, सरकार यह भी चल रही थी। समस्या यह थी कि आपके पास फिस्कल डिसप्लिन नहीं था और यह देखा गया है कि कांग्रेस सरकारें अपनी जरूरत से अधिक कर्जा लेती है और उसकी अदायगी आगे की सरकार को करनी पड़ती है परन्तु मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम कर्जा जितना बन पाएगा लेंगें, जितनी जरूरत होगी, उतना लेंगें लेकिन

आपको अगली बार कर्जा लेने का मौका नहीं देंगें और लम्बे अरसे तक हमारे मुख्य मंत्री की सरकार इस प्रदेश में चलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में गरीब वर्ग, किसान वर्ग, छात्र, युवा कर्मचारी, उद्योगपति सभी का ध्यान रखा गया है ।

12.3.2018/1720/av/ag/1

और इस बजट में विधायकों का भी ध्यान रखा गया है। आपकी विधायक निधि को 1.25 करोड़ रुपये कर दिया गया है, it is a step increase. और यह बढती जायेगी, घटेगी नहीं; मैं आपको यह गांरटी देता हूं। साथ में, हमारी विधायकों की डिस्क्रिशनरी ग्रांट में भी 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, आप इसकी तारीफ क्यों नहीं करते हैं? कर्मचारियों के लिए बजट में 4 प्रतिशत इन्टेरिम रिलीफ दिया गया है; आप कहते हैं कि हम कर्मचारी विरोधी है जो कि कोई लोजिक नहीं बनता है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 225 रुपये कर दी गई है; इस प्रकार की ये छोटी-छोटी बातें हैं जो समाज के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। आप कहते हैं कि हम कर्मचारी और गरीब विरोधी हैं। इसके अतिरिक्त बिना आमदनी के पेंशन की आयु-सीमा घटाकर के 80 वर्ष से 70 वर्ष कर दी गई है जो कि मेरे हिसाब से एक काबिले तारीफ निर्णय है और इससे 1.30 लाख बुजुर्गों को सहारा मिलेगा, आपने इसकी भी कोई तारीफ नहीं की है। मैं मुख्य मंत्री जी का टैक्स फ्री बजट देने के लिए धन्यवाद करता हूं। हां, केवल एक चीज पर इन्होंने टैक्स बढ़ाया है और इस पर टैक्स बढ़ाने के पीछे भी इनकी एक नेक मन्शा थी। उस आइटम को जो कनज्यूम करते हैं उनके हाथ से कम-से-कम एक पुण्य का काम हो रहा है। लिकर पर दो रुपये प्रति बोतल जो टैक्स लगाया गया है उसमें से एक रुपया गो-सदन और एक रुपया हमारे 108 रोगी वाहन के लिए जायेगा। यह बहुत पुण्य का काम है और इसके पीछे हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की उम्दा सोच है जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच का नतीजा है कि हमारी एनुअल प्लान पहली बार 6हजार करोड़ के बैरियर को क्रोस कर गई है। 6 हजार 3सौ करोड़ का यह प्लान साईज है जो कि पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में दिए गए प्लान साईज से 600 करोड़ रुपये ज्यादा है जो कि मैं समझता हूं कि it is

a quantum jump. जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्लान साईज में दिया है, यह तारीफ करने लायक है। मैं मान्य सदन का ध्यान पिछले पांच साल के कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके कारण हमने और प्रदेश की जनता ने कष्ट सहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि हमारी

12.3.2018/1720/av/ag/2

सड़कों की हालत पिछले पांच सालों में बहुत खराब हुई है। क्या आपको पता नहीं है कि पिछले पांच सालों में कैसा कार्य होता रहा? सड़कों को आज पक्का किया जाता था और दस दिनों के भीतर वह उखड़ जाती थी। कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं रह गया, लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार का सैंटर बनकर रह गया है। इस पर कोई चैक नहीं है, (---व्यवधान---) वह हमने बनाई है। Credit goes to previous Chief Minister. हमने प्रार्थना की थी कि लोक निर्माण विभाग में सबलेटिंग का सिस्टम बंद करो। पूर्व मुख्य मंत्री जी मान गये कि कांट्रैक्ट में सबलेटिंग नहीं होनी चाहिए मगर ग्राऊंड पर कुछ नहीं हुआ। वहां एक डिविजन में पूरे साल में 89 ठेके दिए गए जिसमें से 34 ठेके एक ही ठेकेदार को दिए गए। क्या उसके पास इतनी मैन-पावर और मशीनरी हैं कि एक साल में सारे ठेके ठीक करके दे दें। यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार है जिसके लिए हमने मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि इसकी जांच करवाइए। उस एक ही ठेकेदार को 34 ठेके कैसे दे दिए जब यहां पर वर्किंग सीजन ही 4-5 महीने का होता है। मगर उस पर कोई ऐक्शन नहीं हुआ। करप्शन को बढ़ावा देना तो आपका काम रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले पांच सालों में लोगों को बरसात में भी पीने का पानी नहीं मिला। अगर पानी मिला भी तो उसमें शिमला में एक पानी के टैंक में नरकंकाल मिला। आप जनता को किस क्वालिटी का पानी देते रहते हैं? माननीय आई0पी0एच0 मंत्री जी ने एक पीने के पानी का औचक निरिक्षण किया,

12.3.2018/1725/TCV/AG-1

बहुत सारे टैंकों में सफाई ही नहीं हुई। लोग सफाई करने के नाम पर पैसे लेते रहे लेकिन टैंकों की सफाई नहीं हुई, सिर्फ कागज़ों में सफाई होती रही। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए आप लोग जिम्मेवार हैं और अब आप इस बजट की निन्दा करते हैं।

क्या यह सच नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक रेफरल हॉस्पिटल है, जिसमें डेली 600 लोग अपना चैकअप करवाते हैं। आपने वहां पर 15 डॉक्टरों की जगह 6 डॉक्टर रखे। यदि एक डॉक्टर छुट्टी पर चला जाये तो 5 डॉक्टर 600 पैशेंटस को कैसे देखेंगे? इसके बारे में बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी आपकी सरकार (कांग्रेस) ने इसका कोई समाधान नहीं किया। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक बी0एम0ओ0 के अंडर 18 डॉक्टरों के पद सृजित हैं लेकिन वहां पर केवलमात्र 8 डॉक्टर हैं। रिमोट एरिया में भी कोई डॉक्टर नहीं है। एक पी0एच0सी0 ऐसा है, जहां न डॉक्टर है और न ही फार्मासिस्ट हैं और वहां ताला लगा हुआ है। आप कहते हैं, आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी।

शिक्षा के बारे में तो माननीय सदस्य श्री ध्वाला जी ने आपको बड़े विस्तार से बताया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता में यदि कमी आई है, तो आप लोगों की गलत शिक्षा नीति की वज़ह से आई है। जिसकी वज़ह से लाखों छात्र सरकारी स्कूलों से हट करके प्राइवेट स्कूलों में चले गये हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है। इसके लिए आप लोग जिम्मेवार हैं। आपने पिछले 5 सालों में शिक्षा क्षेत्र से खिलवाड़ किया है। आपने जगह-जगह स्कूल खोल दिए और एक बच्चे के लिए 30-40 लाख रुपये प्रतिमाह खर्च कर रहे हैं। Maybe you come to think of it. Is it worth it? Are we getting commensurate results? We are not getting commensurate results. पांचवी कक्षा का छात्र दूसरी कक्षा का टैक्स्ट नहीं पढ़ सकता है। शिक्षा की क्वालिटी डी-ग्रेडेशन के लिए कौन जिम्मेवार

12.3.2018/1725/TCV/AG-2

है। इसके लिए आपकी पॉल्सिस जिम्मेवार हैं। आपके जो रिसोर्सिस थे, उनको आपने थिन-आउट /स्प्रैड कर दिया instead of consolidating and integrating them, आपने differentiate कर दिया, इधर-उधर भेज दिया। आपने ट्राइब्ल एरिया में सारे स्कूल खोल दिए। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी कहते थे कि यदि एक स्कूल में 2 बच्चे होंगे तो मैं वहां स्कूल खोलूंगा। What do you mean? एक बच्चे के लिए आप स्कूल खोलेंगे। वह किसके साथ इंटरैएक्ट करेगा। उसको शरारत करनी है, तो वह किसके साथ शरारत करेगा? उसको कबड्डी खेलनी है, तो वह किसके साथ खेलेगा? बच्चों के बीच में रह कर बच्चा सीखता है। लेकिन आपने जगह-जगह स्कूल खोल दिए without thinking, without any liaising and repercussion of this, कोई नार्मज़ नहीं, नार्मज़ वह होते थे, जो आपके लीडर तय करते थे, that was a norm. मैं आपको बल्द्धवाड़ा, सीनियर सेकैंडरी स्कूल का उदाहरण देना चाहूंगा। उस स्कूल में इन्क्रोचमैंट हुई। मैंने पूर्व मुख्य मंत्री से प्लानिंग की मीटिंग में बात की और बताया कि एक सरकारी कर्मचारी ने इंक्रोचमैंट करके contiguous लैंड पर अपना शोरूम बना दिया है। लेकिन जब हमने शिकायत की तो आपने उस कर्मचारी को नौकरी में एक्सटैंशन दे दी। उसके बदले में स्कूल को एक किलोमीटर दूर ज़मीन दी गई, a Isolated patch of land. आपने कहा इंक्वायरी करवाएंगे, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इसलिए पिछली सरकार ने जो गड्ढा खोदे हैं, उनको भरने के लिए आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने दस्तावेज़ लाया है, ये उसको भरेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या यह भी सच नहीं है कि कांग्रेस के शासन में कोई फिस्कल डिसप्लेन नहीं रहा। आप अंधाधुंध कर्ज़े उठाते रहे और आपने 5 सालों में 18,787 करोड़ कर्ज़ा उठा दिया। आप क्या करते रहे। केन्द्र से आपको कितना पैसा मिलता था? आपने अंधाधुंध तरीके से संस्थान खोल दिए, अपग्रेड कर दिए, with no financial backing, infrastructure and staff. आप करना क्या चाहते थे, उसके लिए आपको वोट तो मिले नहीं। Your approach was failed approach. इसमें कोई शक् की बात नहीं है। भ्रष्टाचार का मामला तो माननीय सदस्य श्री पठानिया

जी ने बहुत अच्छी तरह से उठाया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। आपके दिमाग की मॉनिटरिंग का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपका जो एक सर्वेक्षण आया है, मैंने उसमें पढ़ा है। आपने डेवेल्पमैंट ऑफ इंडस्ट्रीज एरियाज़ लिए 3.50 लाख रुपये अलॉट किए।

12-03-2018/1730/NS/DC/1

साल के तीन क्वार्टर्ज़ में केवल 9.52 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है। यह जो लगभग 13 या 14 करोड़ रुपये की राशि बच गई है क्या यह एक क्वार्टर में खर्च हो जायेगी? There is no checking at all. पिछली सरकार ने माईनर इरिगेशन के लिए स्टेट सैक्टर में 220.75 करोड़ रुपये की राशि अलौट की और साल के तीन क्वार्टर्ज़ में लगभग 54 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। बाकी राशि कब खर्च करेंगे? There is no monitoring. विभागों की फ्लड कंट्रोल पर कोई मोनीटरिंग नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माईनर इरिगेशन में सारी कूहलें बंद पड़ी हुई हैं और वह राशि अल्टीमेटली सरेंडर होगी because that was not been spent. फ्लड कंट्रोल के लिए लगभग 63.50 करोड़ रुपये की राशि मिली और उसमें से केवल 10 करोड़ रुपये की राशि ही खर्च हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीर खड्ड है और उसमें बाढ़ आती है तथा हम उसे रोकने के लिए तरस रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे प्वाईंट्स हैं जिनकी प्रोटैक्शन के लिए हम तरस रहे हैं और यहां पर राशि सरेंडर हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार का क्या सिस्टम रहा है?

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, मैं अब आई0जी0एम0सी0 की बात करने जा रहा हूं। आई0जी0एम0सी0 हमारा प्रीमियर इन्सटीच्यूशन है। आपने इसके लिए लगभग 234.48 करोड़ रुपये की राशि अलौट की और उसमें से केवल तीन क्वार्टर्ज़ में 137 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है। बाकी जो राशि बच गई है आप इसको कब खर्च करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से ये राशि बिना प्लानिंग के खर्च होगी। It is total wastage of public money because there is no checking. हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस बज़ट में Work Management System सुझाया है और आपने इसको अडोप्ट करने की बात कही है और मुझे आशा है कि आप इसको अडोप्ट करेंगे। इसकी प्रोपर

मोनीटरिंग होगी और टैंडर से ले करके कम्पलीशन तक इसकी मोनीटरिंग स्वयं मुख्य मंत्री महोदय करेंगे। यह सिस्ट्म में बहुत इम्प्रूवमैंट है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में केंद्र से कितना पैसा आया है, मैं यहां पर एक छोटा-सा उदाहरण दूंगा। यू0पी0ए0 सरकार के समय में वर्ष 2012-13 से ले करके वर्ष 2014-15 तक केंद्र सरकार ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार को लगभग 28,552 करोड़

12-03-2018/1730/NS/DC/2

रुपये की राशि दी है। लेकिन अगले दो वर्षों में केंद्र की एन0डी0ए0 सरकार ने लगभग 46,793 करोड़ रुपये की राशि दी है। आप स्वयं देखिये कि इसमें कितना फ़र्क है? Where this money has been spent , it is not seen on ground. अध्यक्ष महोदय, कितने नेशनल हाईवेज़ दिये हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं अब अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मैंने यहां पर बताया है कि मेरे क्षेत्र में डॉक्टर्ज़ की कमी है और इसको हम पूरा करेंगे। मेरे क्षेत्र में पानी की भी कमी है। मैं अपने क्षेत्र के लिए कांडापत्तन से तीन स्कीमज़ लाया हूं। मैं एक स्कीम डैहर से लाया हूं। दो स्कीमज़ का माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया था और ये स्कीमें आधी-अधूरी थी। What is this, आप बताईये किसको धोखा दे रहे हैं? आधी-अधूरी स्कीमों का ऑनलाइन उद्घाटन हो गया। प्रदेश में सड़कों की हालत दयनीय है। सीर खड्ड की चैनलाइजेशन का मामला आदरणीय पूर्व विधायक के0डी0धर्माणी जी 15-20 साल पहले से उठाते रहे हैं। वे खुद तो रिटायर हो गये हैं और हम भी रिटायर हो जायेंगे लेकिन सीर खड्ड की चैनलाइजेश्न नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम इसको करेंगे। अगर आप (विपक्ष) के हाथ में कमांड होती तो यह कभी नहीं होता। पांच सालों में एक ऐसी स्कीम जिसका शिलान्यास पूर्व मुख्य मंत्री जी ने किया और पांच सालों में आप उसकी टैक्नीकल सैंक्शन भी नहीं ले सके। आप कितना भेदभाव करते रहे हैं, इस बात का अन्दाज़ा नहीं लगा सकते हैं। सुबह माननीय अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि इस बज़ट में बेरोज़गारों के साथ धोखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि बेरोज़गारों के साथ धोखा किसने किया है? आपने बेरोज़गारों को अलाऊंस देने की बात कही थी कि हम बेरोज़गारों को भत्ता देंगे। आपने जाते-जाते तीन महीने में लगभग 22,000 युवकों को ये भत्ता दिया। आपने यह भत्ता सिर्फ दिखाने के लिए दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि उन 11 लाख बेरोज़गारों का क्या हुआ जो प्रदेश की विभिन्न रोजगार एक्सचेंज़िज में रजिस्टर्ड हैं? अध्यक्ष महोदय, यहां पर सुबह बात हो रही थी कि

आप युवाओं को बिज़नैस फील्ड में डाल रहे हैं। डाइवर्शन होनी चाहिए, entrepreneurship क्या गलत बात है? अगर उनको स्किल दी जाये और उसके बाद वे entrepreneurship की तरफ जायें तो इसमें क्या गड़बड़ी है। I think our Chief Minister doesn't want to give them fish to eat, he wants them to learn how to catch the fish. That is the idea behind it, which you must understand.

12.03.2018/1735/DC/YK-1

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट)....जारी

माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई गई, पैंशन बढ़ाई गई परन्तु उन्हें एरियर नहीं दिया गया। कर्मचारियों को एरियर भी देना चाहिए था। एरियर देना हमारे ऊपर छोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात संक्षेप में रखी है। अभी बहुत कुछ बोलने को है लेकिन मैं समझता हूं कि जो दस्तावेज़ माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है, इसको अगर हम ओपन माइंड से पढ़ेंगे, सही ढंग से पढेंगे तो यह दस्तावेज़ हिमाचल प्रदेश को नई दिशा देगा और हम विकास की ऊँचाइयों में पहुंचेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। यदि आप इसे ब्लॉक माइंड से पढ़ेंगे तो आपको वही नज़र आएगा, जो आप करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री राकेश कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे। श्री राकेश कुमार, सदन में उपस्थित नहीं हैं। आज की चर्चा के लिए जितने नाम हमारे पास आए थे वे पूरे हो गए हैं।

अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, 13 मार्च, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 12 मार्च, 2018 **सचिव।**